सारठ में एक और भूमिहार... | धनबाद में भाजपा की लंगड़ीमार राजनीति... | खूंटी गैंगरेप, चर्च व पत्थलगड़ी का कॉकटेल...

मूल्य : ₹ 20
जुलाई, 2018

समदिया मिथिला

राजनीति गुरु

मिस्फीका के आगे सब फीका

क्रशर पर बुलडोजर

सड़कों पर सियासी नफरत

बड़हरा क्षेत्र के

बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवाओं से

विनम्र अपील...

- मां भारती के सच्चे सिपाही बनें...
- राष्ट्रवादी विचारों के वाहक बनें...
- गंगा मैया के संरक्षण का संकल्प लें...
- गौ माता को बचाने का प्रण करें...
- समावेशी विकास के सहयात्री बनें...

आपका अपना

सूर्यभान सिंह

सेवा-स्वावलंबन प्रमुख
सेवा भारती, झारखण्ड -बिहार

सह संयोजक, नमामि गंगे (बिहार)
क्षेत्रीय प्रभारी, नमामि गंगे (आरा -बक्सर)

समदिया मिथिला
राजनीति गुरु
सियासत जारी है...
जुलाई,2018
www.rajneetiguru.com

संपादक
राघवेंद्र

कार्यकारी संपादक
उदय चौहान

संपादक बिहार
प्रणव

राजनीतिक संपादक
शैलेश तिवारी

समन्वय संपादक
मनोज कुमार सिंह

प्रबंध संपादक
मुकेश मिश्रा

सहायक संपादक
कुणाल कुमार

ब्यूरो प्रमुख
मृत्युंजय श्रीवास्तव
रंजीत झा (संथालपरगना)
उमेश हेलीवाल (धनबाद कोयलांचल)

ऑनलाइन एडिटर
राजीव कुमार

प्रमुख संवाददाता
श्रीधर वत्स, कुमार अमित

सीनियर रिपोर्टर
रतन कुमार, कौशलेंद्र, कुमुद रंजन

क्रियेटिव हेड
सुभाष

असिस्टेंट मैनेजर (मार्केटिंग)
पंकज मिश्रा (पटना)

इस अंक के कंटेंट से संबंधित प्रतिक्रिया और अपने सुझाव इमेल के जरिये भेज सकते हैं। आपके बहुमूल्य सुझाव का इंतजार रहेगा।
contact@rajneetiguru.com

बिहार कार्यालय
जी-603, मुंडेश्वरी इनक्लेव,
आशियाना रोड, पटना

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक-प्रकाशक
राघवेंद्र द्वारा बाबा प्रिंटर्स रामनगरी, आशियाना,
पटना से प्रकाशित एवं मुद्रित

सभी कानूनी मामले पटना के सक्षम न्यायालय द्वारा निपटाये जायेंगे।

आरएनआई नंबर BIHMAI/2010/33053

सियासत का मौसम है..जरा संभलकर

राजनीति भी गज़ब-गज़ब रंग के चादर ओढ़ती और बिछाती है. अभी के झारखण्ड में केसरिया और हरे रंग की सियासी चदरिया से शायद ही कोई अछूता रह गया हो. चुनाव अभी दूर है लेकिन भाजपा और झामुमो ऐसे त्योरियां चढ़ाये हुए हैं, मानो कल ही दो-दो हाथ कर लेंगे.

भूमि अधिग्रहण पर संशोधन ने विपक्ष को एक ऐसा हथियार पकड़ा दिया है, जिसे वो चुनाव तक जिन्दा भी रखेगा और इसी के इर्द-गिर्द अपना चुनावी रथ भी चलाएगा.

इस संशोधन में कई खूबियां भी हैं, कुछ खामियां भी, लेकिन जनता के बीच इसकी गलत व्याख्या कर विपक्ष बस अपनी राजनीतिक रोटी ही सेंक रहा है. इस आपाधापी में आम लोगों के सरोकार फिर हासिये पर. ऐसा लग रहा है, जैसे सबको सत्ता पाने की इतनी हड़बड़ी है कि कोई भी दल कुछ और सुनने को तैयार ही नहीं है. अतिरंजना की यह राजनीति झारखण्ड का गला घोंटने को तत्पर दिखती है.

खैर, समदिया मिथिला राजनीति गुरु के इस अंक में हम आपको एक बार फिर कई राजनीतिक कथाओं से रु-ब-रु करा रहे हैं. पिछले अंक को भी आपने हाथों हाथ लिया था. आपको पता ही है कि बड़ी पूंजी पर आधारित पत्रकारिता के इस मायावी दौर में हम केवल आप पाठकों के संबल का दीया जलाकर बाज़ार में पैर टिकाने की कोशिश कर रहे हैं . हमारी पूंजी केवल और केवल आप हैं. सामने कॉरपोरेट पूंजी का अजगर मुंह बाये खड़ा है. लेकिन सच और आपका संबल हमें पस्त होने नहीं देता. हम कंटेंट की ताकत पर बाज़ार में टिके रहेंगे, यही भरोसा हमारी पूरी टीम को है. लक्ष्य बिलकुल साफ़ है . आम पाठकों तक सच पहुँचाने का सेतु बनना.

इस अंक में भी हमने कई ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश की है जो अमूमन मुख्यधारा की कथित पत्रकारिता में जगह नहीं बना पाते. मसलन संथालपरगना के दम तोड़ते पत्थर उद्योग. प्रदेश के भूमिपुत्रों द्वारा संचालित इस क्रशर उद्योग को सरकारी बुलडोजर से रौंदा जा रहा है. शासन क्रशर संचालकों से ऐसे सलूक कर रहा है जैसे वो पाकिस्तान से आये हों. बिना इनका पक्ष सुने इन्हें उजाड़ा जा रहा है. इस वज़ह से केवल साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका में 5000 से अधिक कामगार बेरोजगार हो चुके हैं. इतनी बड़ी संख्या में बेकार हुए लोग हताश हैं. उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें ! हमने ये पूरा मामला समझने की कोशिश की है. अन्य रपटें भी आपको मिलेगी. बस हम हमेशा की तरह आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करेंगे.

आपका
राघवेंद्र

समदिया मिथिला

राजनीति गुरु

सियासत जारी है...

इस अंक में

सियासी कथा

मिस्फीका ने किया सबको फीका

पेज >> 5-8

सवाल

खूंटी गैंगरेप, चर्च और पत्थलगड़ी का पॉलिटिकल कॉकटेल

पेज >> 42-44

कवर स्टोरी

13-19

राजद में रार

31-33

लेफ्ट पॉलिटिक्स

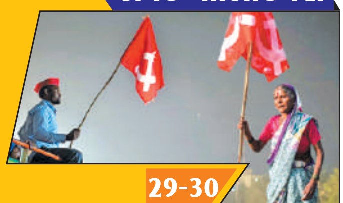

29-30

चक्रव्यूह

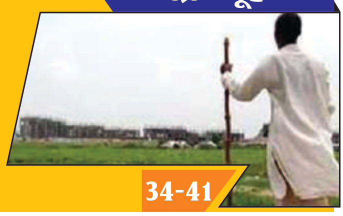

34-41

20

नीतीश कुमार ने तो लालू प्रसाद को कुशल क्षेम के लिए फोन किया था, लेकिन हंगामा क्यों बरपा!

बिहारी राजनीति

23

झारखंड कांग्रेस में किस बात पर है विवाद! प्रदेश अध्यक्ष क्यों हैं घेरे में!

कांग्रेस कंट्रोवर्सी

मिस्फीका ने किया सबको फीका

तीन दशक से अधिक की सक्रिय राजनीति कर चुके पाकुड़ जिला भाजपा के दिग्गजों की हालत वैसे पतंग जैसे हो गई है, जिसके धागे किसी उंचे पेड़ में अटक गए हैं , और पतंग हवा के झोंके खाते- खाते अपने मूलस्वरूप को ही खोने लगी है . पाकुड़ में आज के समय में पुराने कद्दावर नेताओं की गतिविधि ठहर सी गई है. किसी टीवी धारावाहिक की तरह ही पाकुड़ भाजपा में मिस्फीका ने धमाकेदार इंट्री कर सभी को फीका कर दिया है. हाल ऐसा हो गया है कि मिस्फीका के सामने वीआईपी नेताओं की चमक फीकी पड़ जा रही है. रंजीत झा की रिपोर्ट.

पाकुड़ से भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ेगी मुखिया मिस्फीका

दिखने में सुंदर, मृदुभाषी व सरल स्वभाव की मिस्फीका आज पाकुड की राजनीतिक पटल पर छा सी गई है. लगता है भाजपा की गतिविधि मिस्फीका के इर्द गिर्द सिमट सी गई है, बिना इनकी मौजूदगी के सभा शुरू नहीं होती . जिले के उपायुक्त अपने मुख से जनता को मिस्फीका के प्रभावों एवं महत्व को कई जगहों पर बताते भी देखे जा रहे हैं. अब देखना है कि पाकुड़ की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में मिस्फीका को किस प्रकार सिर आंखों पर बिठाती है या फिर कुछ दिन चमक कर ये फिर राजनीति के अंधेरे में कहीं खो जायेगी. फिलहाल पाकुड़ की राजनीति को इन्होंने गर्म तो कर दिया है.

एक मुखिया, जो विधायक से भी अधिक वीआईपी...

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर कौन हैं ये मिस्फीका ! क्या है इनके रुतबे का राज ! ऐसा क्या है कि जिला प्रशासन इनके आगे नतमस्तक है! क्या ये विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी! ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब तलाशने की हमने कोशिश की.

पाकुड़ जिले के सदर अनुमंडल अंतर्गत इलामी पंचायत की मुखिया हैं मिस्फीका. मिस्फीका सन 2015 ई में हुए पंचायत चुनाव में इलामी पंचायत में मुखिया चुनी गई. मात्र 28 वर्ष की इस मुखिया की

महज दो साल में जनप्रतिनिधि के रूप कार्य कर इन्होने ऐसा आभामंडल रचा कि सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास की चहेती जनप्रतिनिधि बन गई.

प्रारंभिक पढाई पं बंगाल के फरक्का स्थित डीपीएस स्कूल में हुई, जहां से 10वीं की परीक्षा पास कर इन्होने रांची से बायो टेक की डिग्री हासिल की . उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से मास्टर डिग्री लेने के बाद नई दिल्ली स्थित एम्स में कैंसर पर रिसर्च की. मिस्फीका कैंसर जैसे खतरनाक व महंगी बीमारी से गरीबों को राहत दिलाने को लेकर भी गंभीर दिखी.

इसी बीच मिस्फीका को अपने गांव आकर पंचायत के माध्यम से गरीबों की सेवा करने की इच्छा जगी और वो मुखिया बन गई. महज दो साल में जनप्रतिनिधि के रूप कार्य कर इन्होने ऐसा आभामंडल रचा कि सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास की चहेती जनप्रतिनिधि बन गई. मुख्यमंत्री इस युवा मुखिया से इतने अधिक प्रभावित हैं कि प्रधानमंत्री के साहिबगंज आगमन पर उन्हें मिस्फीका ने गुलदस्ता दिया, स्वयं मुख्यमंत्री ने ही उसका परिचय भी कराया.

सत्ता से इतनी करीबी पर लोकल भाजपा नेता ही उठा रहे सवाल

पाकुड़ में वर्तमान हालात ऐसे हैं कि जिला प्रशासन के पदाधिकारी से लेकर सीएम कार्यालय तक में मिस्फीका की सीधे इंट्री होती है, जिला प्रशासन के मध्यम व छोटे ओहदेकार मिस्फीका को देखते ही नजरें झुका लेते हैं। एक अदद सुरक्षा गार्ड के लिए कितने आर्थिक व राजनीतिक रूप से सबल आदमी भी जिला प्रशासन से गुहार लगाते थक जाते हैं और मिस्फीका को सीएम से पहली मुलाकात के बाद ही बिना मांग के ही आर्म्स गार्ड उपलब्ध करा दिए गए. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगले विधानसभा चुनाव में पाकुड़ से मिस्फीका ही भाजपा की उम्मीदवार होंगी , रांची में सब कुछ तय किया जा चुका है, इसी मद्देनजर मिस्फीका किसी भी राजनीतिक मंच पर प्रमुखता से देखी जा रही है.

दिखने में सुंदर, मृदुभाषी व सरल स्वभाव की मिस्फीका आज पाकुड की राजनीतिक पटल पर छा सी गई है. लगता है भाजपा की गतिविधि मिस्फीका के इर्द गिर्द सिमट सी गई है, बिना इनकी मौजूदगी के सभा शुरू नहीं होती . जिले के उपायुक्त अपने मुख से जनता को मिस्फीका के प्रभावों एवं महत्व को कई जगहों पर बताते भी देखे जा रहे हैं.

अब देखना है कि पाकुड़ की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में मिस्फीका को किस प्रकार सिर आंखों पर बिठाती है. भले ही मिस्फीका की सक्रिय राजनीति में दमदार इंट्री की चहुंओर चर्चा हो रही है लेकिन उनकी राजनीतिक राह इतनी भी आसान नहीं है. पाकुड़ में सियासी त्रिकोण है. कांग्रेस के आलमगीर आलम अभी विधायक हैं. झामुमो के पूर्व विधायक अकील अख्तर भी चुनाव लड़ने को तैयार बैठे हैं. अगर महागठबंधन के तहत अकील अख्तर को झामुमो ने पाकुड़ से टिकट नहीं दिया तो वो तृणमूल या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं. क्षेत्र में ऐसी ही चर्चा है. अभी जो सूरत बन रही है, उसके अनुसार महागठबंधन से आलमगीर आलम, तृणमूल कांग्रेस से अकील अख्तर और भाजपा से मिस्फीका चुनावी मैदान में हो सकती हैं.

पाकुड़ में अल्पसंख्यक वोटर भाजपा के खिलाफ गोलबंद होकर वोट करते हैं. ऐसे में मिस्फीका को मुसलमानों का वोट नहीं के बराबर मिलेगा. हिन्दू वोटर हमेशा की तरह बटेंगे और इस युवा मुखिया की सियासी राह मुश्किल में पड़ती दिखती है.

अगर ये अपनी छवि के आधार पर मुस्लिम वोट में सेंधमारी कर पाती हैं, तभी इनका कुछ हो सकता है. राजनीति शह और मात का खेल है, जिसमें कब क्या हो, कहना मुश्किल है! लेकिन भाजपा के टिकट के बाद भी जनता का समर्थन आज के हिसाब से कठिन है. राजनीति की इस बिल्कुल नयी खिलाडी की सियासी रणनीति क्या और कैसे बनेगी! इसपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है.

वैसे भी पाकुड़ विधान सभा क्षेत्र की राजनीति थोड़ी उलझी हुयी है. यहां की राजनीति विचारधारा और व्यक्तित्व के बीच गोल-गोल घूमती रही है. पॉलिटिक्स के तीनों सी, कैश,कास्ट और क्राइम का यहां बोलबाला रहा है. इसके बीच से यह महिला कैसे अपना रास्ता बनायेगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा.

देवघर में भाजपा की तीनों सीटों पर रेड अलार्म

रंजीत झा

भाजपा सरकार में शामिल देवघर जिले से दो कैबिनेट मंत्री राज पलिवार एवं रणधीर सिंह के लिए अगली बार अपनी सीट बचाना मुश्किल हो सकता है। बताया जा रहा है कि राजपलिवार को जहां अपनों से ही निपटना होगा, वहीं दूसरी ओर रणधीर सिंह अपने व्यवहार के कारण आरएसएस के निशाने पर हैं।

मंत्री, राज पलिवार

मंत्री, रणधीर सिंह

सूबे के रघुवर दास सरकार में शामिल देवघर जिले से दो कैबिनेट मंत्री राज पलिवार एवं रणधीर सिंह के लिए अगली बार अपनी सीट बचाना मुश्किल दिख रहा है. मधुपुर विधानसभा सीट से 2014 में दूसरी बार जीते राज पलिवार की 2019 के चुनाव में प्रमुख प्रतिद्वंद्वी झामुमो के पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी से कड़ी टक्कर होगी. मंत्री राज पलिवार की संभावित हार में पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की भूमिका से अधिक अपनी व्यक्तिगत कमी तथा भाजपा में भीतरघात का खतरा प्रमुख कारण होने की संभावना प्रबल है.

विधायक, नारायण दास

दो बार मधुपुर विधानसभा सीट से जीत चुके राज पलिवार अपने मृदुभाषी व सरल स्वभाव के कारण ही मतदाताओं को लुभाने में कामयाब रहे थे. वही सरल स्वभाव अब राज पलिवार के लिए मुसीबत बनकर उभर चुकी है, जिसका नतीजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा. हालात ऐसे हैं कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र सहित अनुमंडल मुख्यालय के पदाधिकारियों में मंत्री के आदेशों का कोई असर नहीं दीखता है.

जिले के पदाधिकारी दिखावे के लिए मंत्री का सिर्फ आदर करने की नौटंकी करते हैं, परन्तु उनके आदेशों की अधिकारी तनिक भी परवाह नहीं करते हैं. जनता तो जनप्रतिनिधि के सामने ही दुखड़ा रोती है, हाल यह है कि जनता अपने दुख दर्द एवं समस्या को लेकर मंत्री के पास जाती है, मंत्री उनके समस्या को संबंधित पदाधिकारी के पास निदान के लिए भेजते हैं परन्तु पदाधिकारी इसे गंभीरता से नहीं लेते.

मधुपुर में मंत्री राज पलिवार को अपनों से है ज्यादा खतरा

कहा जा रहा है कि सांसद निशिकांत दूबे के समर्थन वाला गुट इस बार मंत्री को हराने में अहम भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। निशिकांत और राज पलिवार का सियासी बैर जग जाहिर है।

इस वज़ह से जनता की समस्या जस की तस बनी रहती है और मंत्री के प्रति उनका गुस्सा अंदर ही अंदर उबलता रहता है . लोगों को लगता है कि मंत्री ही उनकी समस्या का समाधान नहीं करना चाहते. इसका खामियाजा मंत्री को चुनाव में भुगतना पद सकता है.

ऐसे कई उदाहरण हैं जब मंत्री के आदेश को देवघर में पदाधिकारियों ने कूड़ेदान में फेंक दिया. ऐसी लापरवाही चरम पर है, जिससे जनता की नाराजगी लगातार बढ़ रही है. जिसका खमियाजा निश्चित रूप से अगले चुनाव में मंत्री को ही भुगतना पड़ेगा. मंत्री राज पलिवार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, जिसमें भी पदाधिकारी ही मुख्य कारण बने . ऐसे असहयोगी अधिकारी को मंत्री हटा भी नहीं पाए.

राज पलिवार के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में इनके प्रयास से ग्रिड तो लग गया, परन्तु बिजली की आपूर्ति काफी दयनीय है. 24 घंटे में मात्र 6 से 8 घंटे मुश्किल से बिजली मिल रही है. मंत्री के वादों के बाद भी महिला कॉलेज एवं बहुप्रतिक्षित पार्क का निर्माण कार्य अबतक प्रारंभ नहीं होना चर्चा का विषय बना हुआ है.

अधिकारियों के असहयोग के अलावा मधुपुर भाजपा में दो गुट का सक्रिय होना भी मंत्री के लिए मुसीबत है. चर्चा है कि सांसद निशिकांत दूबे के समर्थन वाला गुट इस बार मंत्री को हराने में अहम भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा. निशिकांत और राज पलिवार का सियासी बैर जग जाहिर है.

इसी कड़ी में मुंबई से ताल्लुकात रखने वाले गंगा नारायण सिंह इन दिनों विधानसभा क्षेत्र में पसीना बहाना शुरू कर चुके हैं, जिन्हें सांसद का भीतरी समर्थन प्राप्त है, इसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है.

आर्थिक रूप से संपन्न गंगा नारायण सिंह का दौरा भाजपा मतदाताओं के बीच अधिक होने के कारण ऐसी चर्चाओं को बल मिल रहा है. साथ ही पिछली बार मंत्री को जिताने में अहम भूमिका अदा कर चुके भूमिहार जाति के सशक्त कार्यकर्ता भी काफी नाराज चल रहे हैं.

वैसे कार्यकर्ता के अनुसार मंत्री के कार्यकाल में उन्हें मंत्री के पावर के अनुसार कामकाज संबंधी लाभ नहीं मिल पाया है. इन सब कारणों से कार्यकर्ताओं के साथ गरीब व मध्यमवर्गीय मतदाता भी इनसे दूर हो रहे हैं, जो संभवत मंत्री के विरोध में वोट कर सकते हैं. मंत्री के लिए आने वाले कम समय में अब आसान नहीं है इतनी बड़ी खाई को पाटना.

सारठ की सियासी पिच पर चौथा भूमिहार

कभी पूर्व विधानसभाध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता का दाहिना हाथ रहे पूर्व जिला परिषद् उपाध्यक्ष परिमल कुमार सिंह उर्फ भूपेन सिंह जो पूर्व विधायक चुन्ना सिंह के भी समर्थकों में रहे हैं, क्षेत्र में ताल ठोक दौरा कर रहे हैं. चर्चा है कि परिमल कुमार सिंह महागठबंधन के नेताओं से गहरे संपर्क बनाए हुए हैं. इस तरह सारठ में रणधीर सिंह, चुन्ना सिंह, शशांक शेखर भोक्ता के बाद चौथे भूमिहार नेता के रूप में परिमल सिंह सामने आ गए हैं.

अब बात सारठ विधानसभा की. सारठ विधानसभा क्षेत्र से झाविमो के टिकट पर जीते विधायक रणधीर सिंह 2014 के चुनाव के बाद ही पाला बदलकर भाजपा में मंत्री पद का मजा जमकर ले रहे हैं. मंत्री रणधीर सिंह सरकार से लेकर क्षेत्र में दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. लगातार क्षेत्र की जनता एवं पदाधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं, परन्तु मंत्री रणधीर सिंह ने जिन मतदाताओं के बीच वर्षों रहकर राजनीतिक सफलता प्राप्त की, चुनाव जीतकर मंत्री पद के लालच में भाजपा में कूद पड़े, जिससे खासकर मुस्लिम मतदाताओं में इनको लेकर काफी नाराजगी है. सारठ विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 40 हजार से अधिक है, जो सारठ के चुनावी जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं, सारठ के मुस्लिम मतदाताओं ने हमेशा ही एकजुटता दिखाते हुए भाजपा के खिलाफ पूर्व विधानसभाध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता या उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह के पक्ष में वोट किया है.

पिछले कई चुनावों पर गौर करें तो सारठ में कभी भी भाजपा उम्मीदवार की सक्रिय भूमिका नहीं रही है, सारठ में अबतक भाजपा का संगठन भी मजबूती से उभर नहीं पाया है. सारठ में झामुमो, झाविमो एवं चुन्ना सिंह का सिक्का चलता आया है. चुन्ना सिंह इस बार भाजपा छोड़ कर पुनः महागठबंधन के संभावित उम्मीदवार रहकर मंत्री को कड़ी टक्कर देने के मूड में हैं. आए दिन क्षेत्र में मंत्री रणधीर सिंह के दूसरे दलों से टिकट की जुगत भिड़ाने की भी चर्चा होती रहती है, जिसके कारण मतदाता असमंजस में रहकर उन्हें विश्वसनीय नहीं मान रहे हैं. साथ ही आरएसएस एवं भाजपा की तीखी नजर भी इनपर है. चर्चा है कि मंत्री रणधीर सिंह का आरएसएस कार्यकर्ता के साथ वर्ताव भी सकारात्मक नहीं रहा है. मंत्री रणधीर सिंह सारठ में 42 हजार मतदाताओं वाले अपने ही जाति भूमिहारों की सहानुभूति पाने में भी अबतक विफल रहे हैं. मंत्री का झुकाव ओबीसी एवं दलित वर्ग जिसकी संख्या लगभग डेढ लाख है की ओर अधिक है. जिसके कारण भूमिहार जाति इनसे दूरी बनाए हुए है.

इस बार महागठबंधन उम्मीदवार भी ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उस हालत में मंत्री का आज का लाल बत्ती वाला रौब काम नहीं आयेगा . मंत्री का गरीब एवं जरूरतमंदों की आर्थिक मदद करके भी उसे तिरस्कृत करने की चर्चा को लेकर मतदाताओं में अंदर ही अंदर विक्षोभ पनप रहा है. वैसे मंत्री रणधीर सिंह अबतक के विधायकों में सबसे अधिक क्षेत्र में काम करने वालों में नाम दर्ज करवा चुके हैं परन्तु चुनावी माहौल को अपने पक्ष में कितना कर पाऐंगे, यह समय ही बता पाएगा. वैसे भी अंत में सबसे अहम यह है कि मंत्री किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे. रणधीर सिंह के विरोध में झामुमो के पूर्व विधानसभाध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता एवं चुन्ना सिंह क्षेत्र में दमदार उपस्थिति के साथ दौरा प्रारंभ कर चुके हैं. कभी पूर्व विधानसभाध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता का दाहिना हाथ रहे पूर्व जिला परिषद् उपाध्यक्ष परिमल कुमार सिंह उर्फ भूपेन सिंह जो पूर्व विधायक चुन्ना सिंह के भी समर्थकों में रहे हैं, क्षेत्र में ताल ठोक दौरा कर रहे हैं. चर्चा है कि परिमल कुमार सिंह महागठबंधन के नेताओं से गहरे संपर्क बनाए हुए हैं. आर्थिक रूप से सशक्त एवं भूमिहार जाति के जाने माने चेहरे के रूप में भूपेन सिंह भी अपने प्रतिद्वदी का खेल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोडेंगे. सारठ के सियासी समर में इस चौथे भूमिहार की चर्चा ने यहां का राजनीतिक माहौल अभी से ही गर्म कर दिया है.

भोलेनाथ के सहारे भाजपा

विधानसभा चुनाव में शहरी मतदाता विधायक के कार्यों के मुल्यांकन के आधार पर ही वोट करती आई है। चर्चा यह भी है कि विधायक नारायण दास उन कथित मौकापरस्त कार्यकर्ताओं के चंगुल में फंस चुके हैं, जो शायद विधानसभा चुनाव में उन्हें अपने समाज में 25 वोट भी नहीं दिला पाऐंगे।

देवघर विधानसभा क्षेत्र से 2014 में जीते भाजपा विधायक नारायण दास की भी राह कठिन ही दिख रही है. विधायक नारायण दास जनता के बीच जाकर समस्याओं को सुनने एवं निदान करने में कम रूचि दिखा रहे हैं. जबकि सांसद की राह पर उनके साथ मंचों पर दिखाई देने में अधिक समय बिता रहे हैं. जिससे खासकर शहरी मतदाता इनसे दूर होते दिख रहे हैं और अब तो मतदाता विधायक के विरोध में साफ बोलते नजर आ रहे हैं. हाल में विधायक का दौरा वैसे क्षेत्रों में अधिक हो रहा है, जहां से उन्हें पिछली बार एक वोट भी नहीं मिला था और न ही आगे मिलने की संभावना ही है. विपक्षी दलों के समर्थकों के बीच अपनी लोकप्रियता की खोज कर रहे विधायक नारायण दास के साथ माया मिली, न राम वाली कहावत सच होने ही वाली है. शहरी क्षेत्रों में विधायक के कर कमलों द्वारा एक भी सार्थक दिखने वाली योजना चर्चा में नहीं है. सच्चाई यह है कि विधायक अपने कट्टर समर्थकों का विश्वास कायम रखने में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं. उन्हें शायद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छवि एवं लहर की आशा है, जो उन्हें हार की ओर ले जा रही है. विधानसभा चुनाव में शहरी मतदाता विधायक के कार्यों के मुल्यांकन के आधार पर ही वोट करती आई है. चर्चा यह भी है कि विधायक नारायण दास उन कथित मौकापरस्त कार्यकर्ताओं के चंगुल में फंस चुके हैं, जो शायद विधानसभा चुनाव में उन्हें अपने समाज में 25 वोट भी नहीं दिला पाऐंगे. आज वैसे ही लोगों के इशारे पर चल कर विधायक अपनी जमी जमाई जमीन खोते जा रहे हैं.

ये है देवघर, सारठ और मधुपुर विधानसभा का हाल. इन सीटों पर भाजपा के लिए लाल बत्ती जलती दिख रही है. अतीत में जो बीमारी कांग्रेस की थी, वही भीतरघात का रोग भारतीय जनता पार्टी को भी लग चुका है. कार्यकर्ताओं के अलग अलग गुट भाजपा विधायकों को हराने के लिए तत्पर दिख रहे हैं. भितरघातियों को पार्टी लाइन की कोई खास परवाह भी नहीं है. अगर अभी भी कुछ बड़ा नहीं किया वर्तमान विधायकों ने तो संभव है भाजपा अगले चुनावों में तीनों ही सीटें लूज कर जाये.

भूमिपुत्रों पर सत्ता का कहर

साहिबगंज, पाकुड, दुमका जिलों में प्रशासन ने जिस प्रकार अवैध खनन एवं अवैध क्रशर के खिलाफ कार्रवाई की है उससे कई सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन सिर्फ छोटे और मध्यम क्रशर के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रही है जबकिबड़े क्रशर और ऑटोमेटिक प्लांट के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है।

रंजीत झा

हाल के दिनों में साहिबगंज, पाकुड़, दुमका जिलों में प्रशासन की ओर से अवैध खनन एवं अवैध क्रशर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सैकड़ों खनन भूखंड को छापेमारी कर सील किया गया और खनन संचालक गिरफ्तार किए गए। अवैध क्रशर के नाम पर चालू क्रशर जेसीबी से ध्वस्त किए जा रहे हैं। हजारों महिला-पुरुष मजदूरों की हंसी-ठिठोली के बीच क्रशर मशीन चलने की आवाज ठहर सी गई है। आज वे हजारों मजदूरों जिनके सुबह का पहला आहार क्रशरों के बीच ही होता था, आज बेरोजगारी की राह पर भविष्य की अंधकार को देख भयभीत हैं।

उनकी कई पीढ़ियों ने इन्हीं क्रशरों में काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजारी है। हजारों मजदूरों का रात दिन इन्हीं क्रशरों के बीच गुजरा है। उनकी आंखों के सामने जिला प्रशासन जिस प्रकार क्रशर मशीनों को ध्वस्त कर रहा है उससे भय का माहौल बन गया है, उसने सपने में भी कभी इस प्रकार की कार्रवाई की बात नहीं सोची थी। रोज क्रशर में काम कर शाम के समय मजदूरी लेकर पेट भरने वाले मजदूरों के सामने भूखमरी की समस्या पैदा हो गई है।

गौर करने वाली बात है कि कार्रवाई उन मध्यम व छोटे क्रशरों पर हो रही है, जो पूरी तरह मैनुअल यानि मजदूरों पर आधारित हैं। बड़े क्रशर तो ऑटोमेटिक प्लांट हैं जहां 5 से 7 लोग ही संचालित कर लेते हैं, वहां मजदूरों की संख्या काफी कम होती है।

मिथिलेश भगत

एक ओर करोड़ों खर्च करके केन्द्र सरकार की ओर से बेरोजगारी दूर करने के लिए सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग लगाने के लिए नई-नई योजनाओं को विज्ञापनों के जरिए दिखाए जा रहे हैं। राज्य की रघुवर सरकार करोड़ों खर्च कर मोमेंटम झारखंड आयोजित कर रही है ताकि निवेशक झारखंड में आएं और उद्योग लगाएं। दूसरी ओर रघुवर सरकार को बड़ा राजस्व देने वाले छोटे व मध्यम क्रशरों को बंद करने की आक्रामक कार्रवाई की सोच कहां से आई? यह लोगों को समझ नहीं आ रही है।

जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई से क्रशर संचालकों में हड़कंप मच गया है, संचालक समूह उपायुक्त से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उपायुक्त न्याय संगत व नियम के तहत कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बता दें कि इस पूरे इलाके से देश के अधिकांश क्षेत्रों में स्टोन चिप्स एवं बोल्डर आपूर्ति होती है। लेकिन आज यहां भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जानकारी के अनुसार, इस परिस्थिति के पीछे सत्ता से जुड़े लोगों का हाथ है। लगभग 8 से 10 दशक से पत्थर व्यवसाय जिले के रग रग में बसा है, आधी आबादी पत्थर व्यवसाय पर निर्भर है और देश व राज्य को अगाध राजस्व के रूप में धन उपलब्ध कराते आ रहा है। फिर अचानक वही खनन क्षेत्र और क्रशर आज अवैध कैसे हो गए ? ताबड़तोड़ छापेमारी और जेसीबी कैसे कहर ढाने लगा।

एक ओर करोड़ों खर्च करके केन्द्र सरकार की ओर से बेरोजगारी दूर करने के लिए सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग लगाने के लिए नई-नई योजनाओं को विज्ञापनों के जरिए दिखाए जा रहे हैं। राज्य की रघुवर सरकार करोड़ों खर्च कर मोमेंटम झारखंड आयोजित कर रही है ताकि निवेशक झारखंड में आएं और उद्योग लगाएं। दूसरी ओर रघुवर सरकार को बड़ा राजस्व देने वाले छोटे व मध्यम क्रशरों को बंद करने की आक्रामक कार्रवाई की सोच कहां से आई? यह लोगों को समझ नहीं आ रही है। आज पीड़ित कारोबारी समूह यह कहने को मजबूर हैं कि अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाली सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है, घोषणाओं और विज्ञापनों के अलग इनकी सत्ता की दबंगई अब गरीबों व मजदूरों पर दिखने लगी है। इन्हें सिर्फ पूंजीपतियों की चिंता है, बड़े औद्योगिक घरानों के हितों की चिंता है। आइए, हम आपको सरकार के क्रियाकलापों का सच बताते हैं कि सरकार कैसे झारखंडवासियों, मतदाताओं व मूलवासियों के खिलाफ अभियान छेड़ चुकी है।

आज जो छोटे व मध्यम क्रशर सरकार और उनके नुमाईंदों को अवैध दिख रहे हैं, वहां सिर्फ कागजों का ही पेंच है। उन कागजों या प्रमाण पत्रों को निर्गत करने वाला खनन विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशैली सभी लोग जानते हैं, विभाग के पदाधिकारियों की निजी संपत्ति की जांच की जाय तो आप सोच भी नहीं सकते कि अरबों की संपत्ति उन्होंने कहां से और कैसे खड़ी की। शायद ही कोई महानगरों में आवास, बैंक लॉकरों में किलो की मात्रा में सोने -चांदी के जेवरात न हों। क्या यह खनन विभाग के पदाधिकारियों की निजी संपत्ति है ? बिना सरकार के शह या मिलीभगत के ये संभव है?

क्रशर के संचालन के लिए सबसे पहली कागजी आवश्यकता प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है जिसके लिए भारी रकम चढ़ावे के साथ लगभग 6 महीने दुमका स्थित प्रदूषण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर रांची मुख्यालय तक का चक्कर काटना पड़ता है। वह भी सिर्फ एक साल की अवधि के लिए मान्य होता है। इसी पेंचीदा कागजी प्रक्रिया में छोटे व मध्यम कारोबारी कमजोर पड़ जाते हैं।

@Rajneeti_Guru @gururajneeti
www. rajneetiguru.com
YouTube Rajneeti Guru Web News Bulletin

इलाके के क्रशर व्यापारियों ने जब कारोबारी स्थानीय विधायक से भी गुहार लगाई तो जवाब मिला कि इस मामले को सीधे मुख्यमंत्री देख रहे हैं, उनके अलावा कोई मदद नहीं कर सकता है।

साहिबगंज जिले के पुराने क्रशर संचालक मिथिलेश कुमार भगत कहते हैं कि आज हमलोगों का अस्तित्व खतरे में है, कई दशकों से पूर्वजों के द्वारा स्थापित क्रशर से ही घर परिवार का भरण पोषण चलता आया है। पुश्तैनी रोजगार पर इतनी बड़ी कार्रवाई से भय का वातावरण बन गया है। हमलोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों से गहरा संबंध जुट चुका था। वह खत्म हो चला है। बिना पूर्व सूचना के ही, बिना समय दिए अचानक जेसीबी से क्रशर को ध्वस्त करना कहां का न्याय है?

श्री भगत आश्चर्य से कहते हैं कि हमलोग झारखंडवासी के साथ-साथ यहां के मतदाता भी हैं, कल तक सरकार के लिए हम सब ठीक थे और आज अचानक गलत हो गए, क्या इन्हीं दिनों के लिए हम व्यवसायी वर्ग झारखंड सरकार की जयकार करते रहे।

बाहरी व पूंजीपति लोग यहां आकर बड़े ऑटोमेटिक प्लांट लगाकर भारी भरकम चढ़ावा देकर घर बैठे कागजी प्रक्रिया पूरी कर पूरे पहाड़ को ही निगल रहे हैं, जिले के प्राचीन पहाड़ों का अस्तित्व समाप्ति के कगार पर है, क्या सरकार को उनसे पर्यावरण की रक्षा हो रही है ? क्या कागजी प्रक्रिया सरल एवं सुलभ बनाने की जिम्मेवारी सरकार की नहीं है ? श्री भगत कहते हैं कि यह सब झारखंडवासियों के विरूद्ध षड्यंत्र हो रहा है। हमलोग सभी कागजी प्रक्रिया पूरी करने को तैयार हैं, सरकार एवं विभाग इसमें मदद करे। छोटे की सुनने वाला कोई नहीं है, पूंजीपतियों की सबलोग सुनते हैं। श्री भगत कहते हैं कि वर्तमान सरकार के मापदंड में अंतर है, नीति स्पष्ट नहीं है, स्थानीय नागरिकों का अस्तित्व समाप्त करने की साजिश चल रही है, व्यवसायी वर्ग अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। अंत में श्री भगत कहते हैं कि सरकार सभी के लिए नियम एक समान छोटे व मध्यम कारोबारी की हैसियत के मुताबिक निर्धारित करे, हम सब पूरा करने का वादा करते हैं।

कारोबारी कहते हैं कि कागजी प्रक्रिया में भारी-भरकम खर्च है जिसे छोटे कारोबारी पूरा करने में असक्षम हो रहे हैं, रोजी-रोटी का सवाल है, विभाग एवं सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए, कागजी प्रक्रिया सहज होनी चाहिए। कागजी प्रक्रिया पूरी तरह भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है।

अन्य एक कारोबारी कहते हैं कि कागजी प्रक्रिया में भारी भरकम खर्च है जिसे छोटे कारोबारी पूरा करने में असक्षम हो रहे हैं, रोजी रोटी का सवाल है, विभाग एवं सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए, कागजी प्रक्रिया सहज होनी चाहिए। कागजी प्रक्रिया पूरी तरह भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है, सरकार या तो इसमें शामिल है या भ्रष्टाचार समाप्त करने में पूरी तरह असक्षम है।

प्रतिष्ठित क्रशर व्यवसायी प्रकाश केडिया कहते हैं कि सरकार का नियम मानना सभी का दायित्व है, नियम के अनुसार काम होना चाहिए, विभाग को भी इसमें मदद करनी चाहिए। प्रक्रिया सहज व सरल होने से कारोबार में वृद्धि होगी और सरकार को भी राजस्व से अच्छी आमदनी होगी।

संथाल के क्रशर मालिकों पर सरकार का हथौड़ा

राज्य सरकार पूरे तामझाम के साथ वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन करती है। कहा जाता है कि इससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। राज्य में खुशहाली आएगी। दूसरी तरफ झारखंड के स्थानीय क्रसर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। संथाल परगना के सैकड़ों क्रशर बंद कर दिए गए हैं और इस वजह से हजारों कामगार सड़क पर आ गए हैं। यह किस प्रकार का विकास है कि एक तरफ उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है वहीं दूसरी ओर सालों से काम करे रहे छोटे-छोटे उद्योगों को उजाड़ा जा रहा है। **मनोज सिंह की रिपोर्ट**

बाहर से सरकार व्यवसायियों को झारखंड में आमंत्रित कर रही है। उनका रेड कार्पेट वेलकम हो रहा है, दूसरी तरफ झारखंड के स्थानीय क्रशर मालिकों पर सरकार का मनमाना डंडा चल रहा है।

राज्य सरकार के तामझाम वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के बाद भी झारखंड में गिने चुने ही निवेशक आए। यह कितनी दुखद बात है कि एक तरफ झारखंड सरकार बाहर से व्यवसायियों को झारखंड में आमंत्रित कर रही है। उनका रेड कार्पेट वेलकम हो रहा है, दूसरी तरफ झारखंड के स्थानीय क्रशर मालिकों पर सरकार का मनमाना डंडा चल रहा है।अभी तक संथाल परगना के सैकड़ों क्रशर बंद कर दिए गए हैं और इस वजह से हजारों कामगार सड़क पर आ गए हैं। उनके घर का चूल्हा भी ठीक से नहीं जल रहा है, परेशान क्रशर मालिकों ने खनन विभाग से और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण और खनन विभाग के अधिकारी कागजी जटिलताओं की आड़ में अभी भी क्रशर ऑनर्स के प्रति दोहरा रवैया अपना रहे हैं। इसे लेकर संथाल परगना के साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका में स्थानीय लोगों में आक्रोश है।

क्रशर व्यवसाय से जुड़े लोग आरोप लगा रहे हैं कि पिछड़ी जाति और आदिवासी उद्यमियों की वजह से इस उद्योग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

यह उद्योग झारखंड सरकार को रॉयल्टी तो देता ही है, साथ ही हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार भी देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिला प्रशासन इस उद्योग के प्रति ऐसा रवैया क्यों रखता है! अधिकांश क्रशर मालिक प्रदूषण नियंत्रण के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर चुके हैं। महीनों दौड़ने के बाद भी उन्हें अगर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो क्या प्रदूषण नियंत्रण के जिम्मेदारों पर कार्यवाई नहीं होनी चाहिए! जहां तक माइनिंग लीज का सवाल है, उसकी जिम्मेवारी जिले के माइनिंग अधिकारियों की होती है, अगर कोई उद्योग माइनिंग लीज की तमाम अहर्ता पूरी नहीं करता तो उन्हें नोटिस किया जाना चाहिए। अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिए। यही नैसर्गिक न्याय का तकाजा है और कानून भी। लेकिन बिना किसी मजबूत वजह के जिला प्रशासन का टास्क फोर्स ऐसे उद्योगों को बंद कर रहा है। यह मनमानी बंद होनी चाहिए।

संथाल परगना के भूमि पुत्रों का एकमात्र व्यवसाय धीरे-धीरे तबाह हो रहा है और इनकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है। हजारों लोगों का रोजगार बंद हो चुका है। सभी स्थानीय विधायक खामोश हैं। यहां तक की क्षेत्र के नौजवान बैंक से लोन लेकर रोजी-रोटी कमाने की लालसा में लोन के चक्रव्यूह में फंस कर जगह जमीन बेचने पर मजबूर हो रहे हैं।

प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, उसकी जमीनी हकीकत की पड़ताल जब की गयी तो पता चला कि जब भी साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका के डीसी का तबादला होता है, उसके तुरंत बाद सबसे पहली कार्रवाई मांइस कारोबारियों को झेलनी ही पड़ती है।

उपायुक्त खनन विभाग के पदाधिकारी को बुलाकर विभाग की समीक्षा करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस क्रशर मालिक का पेपर अधूरा है! उसके बाद उनका मौखिक निर्देश आता है कि क्रशर को अविलंब बंद कर दिया जाए। क्रशर एसोसिएशन के लोग दौड़े भागे खनन पदाधिकारी के ऑफिस का चक्कर लगाने लगते हैं और उसके बाद तोल-मोल करके नए हाकिम का नया रेट तय होता है और फिर काम चालू हो जाता है। इसी क्रम में कुछ ऐसे उपायुक्त भी आ जाते हैं, जो अपनी मनमर्जी से माइंस लीज देना बंद कर देते हैं अथवा कुछ तकनीकी आधार पर कमी दिखा कर फाइल को दबा देते हैं। आखिर इस अराजकता और मनमानेपन के पीछे पदाधिकारियों की मंशा क्या है।

लेकिन वास्तविक सचाई यही है कि हर हाल में संथाल परगना के भूमि पुत्रों का एकमात्र व्यवसाय धीरे-धीरे तबाह हो रहा है और इनकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है। हजारों लोगों का रोजगार बंद हो चुका है। सभी स्थानीय विधायक खामोश हैं! यहां तक की क्षेत्र के नौजवान बैंक से लोन लेकर रोजी- रोटी कमाने की लालसा में लोन के चक्रव्यूह में फंस कर जगह जमीन बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। मजदूरों का क्षेत्र से पलायन हो रहा है।

पाकुड़ जिले में पैनम कंपनी के बंद होने के बाद हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे, उस पर पत्थर उद्योग की बर्बादी ने हजारों नौजवानों को बेरोजगारी के तपते बालू के बीच में खड़ा कर दिया। क्षेत्र के मजदूर और नौजवान नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा।

जब पेट की आग दिमाग तक पहुंच जाती है, उसी वक्त एक नई क्रांति अपना स्वरूप लेने लगती है कहीं ऐसा ना हो की भूमि पुत्र क्रशर मालिक अपनी तबाही से तंग आकर व्यवस्था के विरुद्ध करो या मरो का बिगुल फूंक दें।

आये दिन पाकुड़, बरहरवा, तीनपहाड़, साहेबगंज रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मजदूर कमाने के लिए केरल, मुंबई ,दिल्ली और पंजाब की ओर चले जा रहे हैं।

स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर भाषण देने वाले संथाल परगना के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता इन भूमि पुत्रों की बर्बादी पर धृतराष्ट्र बने हुए हैं। राज्य के आला अफसर भी चुपचाप तमाशा ही देख रहे हैं। कहा जाता है कि जब पेट की आग दिमाग तक पहुंच जाती है, उसी वक्त एक नई क्रांति अपना स्वरूप लेने लगती है कहीं ऐसा ना हो की भूमि पुत्र क्रशर मालिक अपनी तबाही से तंग आकर व्यवस्था के विरुद्ध करो या मरो का बिगुल फूंक दें। पत्थलगड़ी की जगह कहीं नयी क्रशरगड़ी ना शुरू हो जाये संथाल में।

वक्त की जरुरत है कि मृतप्राय और बर्बाद हो रहे पत्थर उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा समेकित कदम उठाया जाय और सिंगल विंडो सिस्टम की तर्ज पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स बनाकर उनकी समस्या का समाधान किया जाए।

संथाल परगना में पत्थर उद्योग से सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला पाकुड़ है, लेकिन विगत कुछ महीनों से पाकुड़ का पत्थर उद्योग पूरी तरह से चरमरा गया है. सरसरी तौर पर देखा जाए तो इस उद्योग की बर्बादी के पीछे राजनीतिक साजिश की बू आती है, क्योंकि लिट्टीपाड़ा उपचुनाव राज्य सरकार की नाक की लड़ाई थी, लेकिन अपना पूरा दमखम लगाने के बावजूद भाजपा लिट्टीपाड़ा से चुनाव हार गई.

चुनाव हारने के बाद कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए, जिससे यह पता चलता है कि पाकुड़ का पत्थर उद्योग किसी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बना. पाकुड़ जिले में उपायुक्त के पद पर दिलीप झा जैसे अधिकारी को पदस्थापित किया गया. उपायुक्त और एसडीओ जितेंद्र देव ने मिलकर सघन छापामारी अचानक शुरू कर दिया. जिस किसी भी क्रशर मालिक के पास छोटे-मोटे कागज नहीं मिले, उनके क्रशर को सील कर दिया गया और यह क्रम लगातार चलते रहने से क्रशर मालिकों में हड़कंप मच गई और इलाके का फलता-फूलता उद्योग धीरे-धीरे बर्बादी की कगार पर चला गया. पाकुड़ जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 3 पर झामुमो और एक पर कांग्रेस का कब्जा है. वर्तमान सत्ताधारी दल लिट्टीपाड़ा में सारी ताकत लगाने के बाद जब चुनाव हार गया तो उसके बाद कुछ छुटभैया नेताओं ने मुख्यमंत्री और उनके सलाहकारों को यह समझा दिया कि पत्थर व्यवसायियों ने भाजपा के विरोध में काम किया है. कुछ ऐसे नेता अपने निजी स्वार्थ के चलते अथवा व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलने के कारण पत्थर व्यवसायियों से अंदर ही अंदर खुन्नस रखते थे और जैसे ही उनको मौका मिला, उन्होंने क्रशर मालिकों के खिलाफ षड्यंत्र कर दिया.

पहले से आहत भाजपा के बड़े नेताओं ने इन छुटभैया नेताओं की बात को सही समझते हुए उन व्यापारियों को सबक सिखाने का मन बना लिया और दिलीप झा का पदस्थापन उसी कड़ी का एक हिस्सा माना जाता है. पाकुड़ जिले में पैनम कंपनी के बंद होने के बाद हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे, उस पर पत्थर उद्योग की बर्बादी ने हजारों नौजवानों को बेरोजगारी के तपते बालू के बीच में खड़ा कर दिया. क्षेत्र के मजदूर और नौजवान नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा! पत्थर उद्योग एसोसिएशन के जानकारों का कहना है कि हम लोग केवल अपना धंधा करते हैं, हम लोगों को राजनीति से कुछ लेना-देना नहीं है बल्कि यह सारा उद्योग राजनीति का शिकार होकर बर्बाद हो चुका है. सैकड़ों माइंस बंद कर दिए गए हैं और हजारों ट्रक माल जो प्रतिदिन बंगाल और बिहार जाता था, वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका है. ट्रक मालिक पाकुड़ से सामान नहीं मिलने के चलते अपनी गाड़ियों को लेकर कहीं बाहर चले गए हैं लेकिन पाकुड़ जिला के स्थानीय ट्रक मालिक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करें! धीरे-धीरे फाइनांस कंपनियों का दबाव बढ़ता जा रहा है और किस्त नहीं जमा करने के चलते उनकी गाड़ियां उठा ली जा रही हैं. कई लोग तो अपना घर-जमीन बेच कर भी गाड़ी का किस्त नहीं चुका पा रहे हैं.

@Rajneeti_Guru @gururajneeti
www. rajneetiguru.com
YouTube Rajneeti Guru Web News Bulletin

झारखंड यादव महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बजरंगी प्रसाद यादव कहते हैं कि क्रशर उद्योग के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है. क्रशर मालिकों को बिना उनका पक्ष सुने प्रताड़ित किया जा रहा है. ज्यादातर पिछड़े और आदिवासी क्रशर उद्योग से जुड़े हैं, भाजपा को लगता है कि पिछड़े उनके समर्थक नहीं हैं, इसलिए भी राज्य सरकार इन्हें प्रताड़ित कर रही है. यह उद्योग परेशानियों के बाद भी सरकार को सबसे अधिक राजस्व देता है. इस उद्योग से जुड़े अनापत्ति प्रमाण पत्रों के लिए प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाना चाहिए. भूमिपुत्र क्रशर मालिकों के साथ हर हाल में न्याय होना चाहिए.

पाकुड़ की यह भयावह स्थिति जिस भी कारण से पैदा हुई हो, क्षेत्र के लिए बहुत दुखद है पाकुड़ के बुद्धिजीवी और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि सरकार ने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया है तो फिर लोग अपनी समस्या लेकर कहां जाएं!

हो सकता है कि कुछ विपक्षी पार्टी के लोग व्यापार को बदनाम करने की नीयत से प्रोपेगंडा फैला रहे हों, फिर भी पत्थर व्यवसायियों की सुनने वाला आज कोई नहीं है. सरकार को इन व्यवसायियों के साथ बैठकर उनकी समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठाना चाहिए क्योंकि यदि सरकार की नीयत राज्य में उद्योग धंधे स्थापित कर रोजगार को बढ़ावा देने की है तो फिर संथाल परगना के इन भूमि पुत्रों के द्वारा दशकों से चलाए जा रहे पत्थर उद्योग को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है.

निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि या तो सरकार की नीति में कोई गलती है या जिला के खनन पदाधिकारी इस बर्बाद होते व्यवसाय के संबंध में अपनी कोई राय देना नहीं चाहते हैं. उनका स्पष्ट कहना है कि वे वही कदम उठाते हैं जिसका निर्देश उपायुक्त और राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा उन्हें मिलता है. पत्थर उद्योग में पाकुड़ स्टोन का पूरे देश में नाम है और यहां का पत्थर चिप्स के रूप में सर्वविदित है. लेकिन आज अपने बेहतर क्वॉलिटी के बावजूद भी पाकुड़ स्टोन से जुड़े हुए लोग अपना धंधा पानी बंद कर कोलकाता या किसी अन्य जगह पर पलायन के लिए विवश हो रहे हैं, क्योंकि रोज-रोज प्रशासन की दखलंदाजी और उनके द्वारा उठाए जा रहे विध्वंसकारी कदम के चलते वह अंदर से टूट चुके हैं. इनकी व्यथा को सुनने वाला कोई नहीं है. इनसे बात करने पर उनका दर्द साफ-साफ दिखाई देता है. पाकुड़ में कभी सिंधी समाज समृद्ध माना जाता रहा और इसी सिंधी समाज ने पाकुड़ में पत्थर व्यवसाय की शुरुआत भी की थी. लेकिन आज गिने-चुने सिंधी समाज के लोग पाकुड़ में रह गए हैं बाकी अपना घर बार धंधा पानी बेचकर ज्यादा से ज्यादा लोग कोलकाता में शिफ्ट कर गए हैं और यह क्रम लगातार जारी है. महेशपुर, लिट्टीपाड़ा और पाकुड़ के विधायक से जब इस संबंध में संपर्क किया गया तो सीधे तौर पर उन्होंने किसी पार्टी या सरकार पर आरोप तो नहीं लगाया लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार किया कि प्रशासनिक दखलंदाजी के चलते पाकुड़ का पत्थर उद्योग बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है. इसे बचाया जाना चाहिए. सरकार को टास्क फोर्स बनाकर इन पत्थर व्यवसायियों के साथ बैठक करनी चाहिए और उनकी जो भी समस्या हो उसके निराकरण के दिशा में कदम उठाना चाहिए. इन विधायकों ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार के संज्ञान में हम लोगों ने बात को नहीं रखी है बल्कि सरकार ने हम लोगों के अनुरोध को अनसुना कर दिया. पाकुड़ के सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग क्षेत्र के मजदूरों और बेरोजगार नौजवानों की दुर्दशा पर अफसोस जाहिर करते हुए यह कहते हैं कि कभी पाकुड़ रात दिन गुलजार रहता था और यहां की दुकानें और होटल खुले रहते थे. आज 8 बजे रात के बाद शहर में सन्नाटा छा जाता है. सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और कोई चहल-पहल नहीं दिखाई देता है.

कई सामजिक संगठनों ने यहां के नौजवानों की दुर्दशा को बयां करते हुए बताया कि यदि आप उनकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन पर चले जाइए! आप देखेंगे कि प्रतिदिन सैकड़ों नौजवान रोजगार की तलाश में दूसरे शहर की ओर पलायन कर रहे हैं.

स्टेशन की तहकीकात करने पर उन लोगों की बात सच साबित होती दिखी, स्टेशन पर खड़े कुछ नौजवानों से बात करने पर यह सच्चाई सामने आई. उन्होंने कहा कि वे लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे लेकिन यहां के स्थानीय ट्रक मालिक या तो अपने ट्रकों को बेच रहे हैं या फिर दूसरे शहरों में जाकर अपना धंधा कर रहे हैं, इसलिए उनकी नौकरी चली गई है और जिस प्रकार पैनम और पत्थर उद्योग दोनों लगभग बंद हो चुके हैं, वैसी स्थिति में निकट भविष्य में किसी रोजगार की संभावना भी नहीं दिखती है.

नीतीश ने किया फोन... लालू ने पूछा, आप कौन !

26 जून को सीएम नीतीश कुमार ने राजद प्रमुख लालू यादव से फोन पर बात की, उनसे उनकी सेहत के बारे में पूछा। पर इस बातचीत से बिहार से सियासत में एकबारगी कयासों का बाजार गर्म हो गया। कहा जाने लगा कि नीतीश के दिल में लालू के प्रति आई ये हमदर्दी कुछ और गुल खिलाने वाली है। आखिर चार महीने बाद नीतीश को लालू की याद क्यों आयी। नीतीश के मन में क्या है ये तो वही बेहतर जानते हैं। पर इस मुद्दे पर सियासत जारी है...

कुणाल

लालू के जेल जाने से लेकर उनकी बीमारी के बारे में पता चलने तक कभी भी सीएम नीतीश कुमार लालू को फोन नहीं किया और न ही किसी प्रकार की कोई बात की, हां उनके बड़े बेटे तेजप्रताप की शादी में शरीक जरूर हुए पर इस दौरान किसी तरह की कोई खास बातचीत नहीं की, फिर अचानक उनकी सेहत को लेकर चिंता दिखाने से सियासी महकमे में खुश फुसाहट तेज हो गई।

बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों ही ओर से चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में अंदरूनी खींचतान जारी है। जहां एक ओर जदयू लगातार अपने बयानों के जरिए भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से इस मामले को लेकर कोई खआस तवज्जो नहीं दी जा रही है। भाजपा की ओर से किसी नेता ने सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई विशेष टिप्पणी भी नहीं की है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि एनडीए में किसी भी प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति नहीं है और आनेवाले समय में जब दोनों पार्टियां आमने-सामने बैठेंगी तो सीट बंटवारे को लेकर बात भी हो जाएगी। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए के प्रमुख चेहरा हैं और सूबे में चुनाव भी उनके चेहरे पर ही लड़ा जाएगा।

लेकिन सियासी गलियारों में जिस प्रकार की चर्चा हो रही है वह इतना सीधा और स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। खासकर तब जब जदयू के कई नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर तल्ख बयानबाजी कर दी है। खुद सीएम नीतीश कुमार ने कहा दिया है कि इस बार लोकसभा का चुनाव 2014 की तरह आसान नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर सवाल उठाते हुए चेताया भी है कि ऐसी भूल करने से भाजपा को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। देखा जाय तो जदयू ने एक तरह से यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भाजपा के सियासी पैंतरे को वह किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि भाजपा की ओर से अभी तक सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं की गई है और माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभी समय है और आलाकमान कोई स्पष्ट निर्णय लेगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आए।

इन सब के बीच राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है कि क्या सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन में शामिल होने की जुगत में हैं। इस बात को बल तब मिला जब नीतीश कुमार ने पिछले दिनों राजद प्रमुख लालू यादव से फोन पर उनकी सेहत को लेकर बात की।

बताया जा रहा है कि लालू के जेल जाने से लेकर उनकी बीमारी के बारे में पता चलने तक कभी भी सीएम नीतीश कुमार लालू को फोन नहीं किया और न ही किसी प्रकार की कोई बात की, हां उनके बड़े बेटे तेजप्रताप की शादी में शरीक जरूर हुए पर इस दौरान किसी तरह की कोई खास बातचीत नहीं की, फिर अचानक उनकी सेहत को लेकर चिंता दिखाने से सियासी महकमे में खुशफुसाहट तेज हो गई।

कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार यूं ही बिना कारण फोन नहीं किया करते जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। भाजपा की ओर से सीट बंटवारे को लेकर हो रही खींचतान के बीच उन्होंने महागठबंधन की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है।

इस नए कयास पर जदयू और राजद के नेता आपस में भीड़ गए और कह डाला की ये संभव नहीं है। जदयू ने जहां ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया और कहा कि भ्रष्टाचार के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। जदयू आगामी लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेगा। वहीं, दूसरी ओर राजद ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एक साथ कई आरोपों की झड़ी लगा दी और कहा कि नीतीश कुमार ने भरोसा खो दिया है।

सीएम नीतीश के खिलाफ सबसे पहले राजद नेता तेजस्वी ने ही हमला बोल दिया उन्होंने कहा कि जनादेश का अपमान कर जनता के साथ धोखा देने वाले और 36 घोटाले करने वाले नीतीश कुमार के लिए महागबंधन में कोई जगह नहीं है इसलिए उनके लिए महागठबंधन का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। यदि नीतीश कुमार को फिर से महागठबंधन में

कांग्रेस के लोग इस बात को भूले नहीं होंगे कि जब भोजन पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मुलाकात हुई थी तब जदयू के लोगों ने कहा था कि यह दो भ्रष्टाचारियों का मिलन है। उन्होंने कहा कि चुनावी गठबंधन के संबंध में जो लोग फैसला लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं उनके बयानों का कोई अर्थ नहीं है। इस मामले में राहुल गांधी ही फैसला लेंगे और उन्होंने उनसे मुलाकात के दौरान साफ शब्दों में कहा है।

शामिल कराया जाता है तो बिहार की जनता भी महागठबंधन को माफ नहीं करेगी। जनता राजद को भी पलटीमार कहने लगेगी।

वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस की ओर से नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल करने का दबाव बनाया जायेगा तो भी वह नहीं मानेंगे। वह कई बार साफ तौर पर कह चुके हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को महागठबंधन में शामिल करने का कोई प्रस्ताव आता है तो वह उसका विरोध करेंगे। वैसे राजद के सभी सहयोगी दल नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को फिर से महागठबंधन में शामिल किये जाने के खिलाफ हैं। तेजस्वी ने कहा है कि कांग्रेस यदि नीतीश कुमार के संबंध में उनसे राय लेगी तो वह बतायेंगे कि नीतीश कुमार विश्वासघाती हैं।

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों तथा जनता को भी धोखा दिया है। कांग्रेस के लोग इस बात को भूले नहीं होंगे कि जब भोजन पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मुलाकात हुई थी तब जदयू के लोगों ने कहा था कि यह दो भ्रष्टाचारियों का मिलन है। उन्होंने कहा कि चुनावी गठबंधन के संबंध में जो लोग फैसला लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं उनके बयानों का कोई अर्थ नहीं है। इस मामले में राहुल गांधी ही फैसला लेंगे और उन्होंने उनसे मुलाकात के दौरान साफ शब्दों में कहा है कि उनकी पार्टी की राजद के साथ लंबे समय तक साथ चलने की योजना है।

नीतीश कुमार जहां जायेंगे सबको डुबायेंगे। ऐसे व्यक्ति को कोई भी अपने साथ नहीं रखना चाहेगा जो विश्वासघात करता हो। इसके साथ ही कहा है कि नीतीश कुमार का अब बिहार में कोई राजनीतिक आधार नहीं रह गया है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अकेले लड़ी तब 135 विधानसभा सीटों पर उसके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गयी।

नीतीश कुमार का भाजपा से एक बार फिर मोहभंग हो गया है इसलिए वह एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी में हैं। जबकि उन्होंने ही भाजपा को चोर दरवाजे से सत्ता में वापस लाया है। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर जदयू -बीजेपी के बीच रार के बीच कभी नीतीश के बेहद करीबी रहे और फिर बाद में सियासी 'दुश्मन' बने मांझी ने उन्हें सशर्त महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है पर तेजस्वी के रुख से वे शायद अपने पैर खींचने से गुरेज नहीं करेंगे।

इसके साथ ही लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप ने भी नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। तेजप्रताप ने कहा है कि वह पटना में अपने घर के बाहर 'नीतीश चाचा' के लिए 'नो-एंट्री' का नोटिस बोर्ड लगाएंगे। उन्होंने कहा, 'नीतीश चाचा के लिए नो एंट्री एक बड़े नोटिस बोर्ड पर लिखी जाएगी और इसे 10 सर्कुलर रोड बंगले के बाहर लगाया जाएगा। 10, सर्कुलर रोड बंगले में लालू का परिवार रहता है। ये बंगला तेजप्रताप की मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित किया गया था। उन्होंने कहा कि जब हम उन्हें अपने घर में ही प्रवेश की इजाजत नहीं देंगे, तो महागठबंधन में प्रवेश कैसे हो सकता है।

अपने कुनबे को कैसे संभालेंगे डॉ अजय !

जहां एक ओर राज्य की सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हैं, इसको लेकर रणनीति बना रही हैं। वहीं कांग्रेस आपसी गुटबाजी और अंदरुनी लड़ाई में व्यस्त है। पार्टी नेता आपसी विवाद को सुलझाने में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस की कमान जब डॉ अजय कुमार के हाथों में सौंपी तो ऐसा लग रहा था कि कुछ हद तक पार्टी में कलह थमेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक बार फिर स्थिति बिगड़ती जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश अध्यक्ष के बीच विवाद गहराता जा रहा है। ऐसे समय में जब अंदरूनी विवाद को किनारे रखकर मिशन 2019 की तैयारी में लगने का समय है पार्टी के सीनियर नेता प्रदेश अध्यक्ष के साथ दो-दो हाथ करने के मूड में हैं। **उदय कुमार चौहान** की रिपोर्ट।

कांग्रेस कंट्रोवर्सी

मिशन 2019 की तैयारी में सभी दल जुट गए हैं, कोशिश की जा रही है कि अपने दल को दुरुस्त कर चुनावी मैदान में पूरे दमखम से उतरा जाए। प्रदेश कांग्रेस में भी इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि प्रदेश स्तर से लेकर जिला और प्रखंड स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाए। कार्यकर्ता और नेता इसको लेकर काफी सक्रिय हैं और हाल के दिनों में सरकार विरोधी धरना-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि संगठन में बदलाव आया है।

इन सब के बीच कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस की कमान डॉ अजय कुमार के हाथों में सौंप दी और पार्टी को सजाने-संवारने की जिम्मेदारी सौंपी। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला लेकिन जैसे ही नए प्रदेश अध्यक्ष ने पुराने नेताओं से पूछताछ करना शुरू किया, धीरे-धीरे विवाद बढ़ता गया। रही सही कोर-कसर जिलाध्यक्षों ने पूरी कर दी। कहा गया कि डॉ अजय पार्टी के पुराने नेताओं से किसी भी प्रकार का राय मशवरा नहीं करते सिर्फ

कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान के बीच डॉ अजय के खिलाफ उनके अपने ही दल के लोग उन पर अपनी पार्टी को कमजोर करने के आरोप लगाते रहे हैं पिछले दिनों हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था।

कुछ आधारहीन नेताओं से घिरे हुए हैं।

डॉ अजय पर कांग्रेस नेता सुनील सिंह ने तो जान से मारने की धमकी की बात कही। उन्होंने कहा कि डॉ अजय शूट करने की बात करते हैं, कांग्रेस में इस प्रकार का कल्चर कभी नहीं रहा है कि अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को शूट करने की धमकी दी जाए। पार्टी के कुछ नेता डॉ अजय पर बाहरी होने का भी आरोप लगाते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें कांग्रेस की राजनीति के बारे में कुछ भी पता नहीं है।

कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान के कारण ही कहा जा रहा है कि जब दिल्ली में प्रदेश के बड़े नेताओं को प्रभारी आरपीएन सिंह ने मीटिंग के लिए बुलाया तो कई नेताओं ने इसमें शामिल होना भी मुनासिब नहीं समझा और साफ कन्नी काट गए। कहा जा रहा है कि प्रदीप बलमुचू, मन्नान मलिक, सुबोधकांत सहाय, ददई, दुबे और राजेंद्र सिंह जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का बुलाए जाने पर भी नहीं जाना पार्टी के लिए खतरे के संकेत हैं। ऐसे समय में जब अंदरूनी विवाद को किनारे रखकर मिशन 2019 की तैयारी में लगने का समय है पार्टी के सीनियर नेता प्रदेश अध्यक्ष के साथ दो-दो हाथ करने के मूड में हैं।

अब एक नया विवाद शुरू हो गया है और इससे लगता है कि पार्टी के सीनियर नेता अब किसी भी हाल में अपने अध्यक्ष को बख्शने को तैयार नहीं हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर अब लेटर वार शुरू हो गया है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय ने वरिष्ठ नेताओं की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पत्र लिखा, तो दूसरी तरफ वरिष्ठ नेताओं ने भी पत्र के माध्यम से इसका जवाब दिया है।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है तो इससे पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता सह पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की कार्यशैली को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए थे। हालांकि केएन त्रिपाठी ने इस बाबत कहा था कि यह संगठन का मामला है इसे सुलझा लिया जाएगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अजय ने पिछले दिनों समन्वय समिति की बैठक को लेकर वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर पत्र लिखा था तो वहीं उसके जवाब में भी सुबोध कांत सहाय ने पत्र लिखा है। प्रदेश कांग्रेस में नए पदों की घोषणा के बाद से ही संगठन में लगातार प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के बीच विवाद दिख रहा है। लगातार एक दूसरे की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है तो इससे पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता सह पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की कार्यशैली को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए थे। हालांकि केएन त्रिपाठी ने इस बाबत कहा था कि यह संगठन का मामला है इसे सुलझा लिया जाएगा।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने खुल कर कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अकेले संगठन चलाना चाहते हैं जो संभव नहीं है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी संगठन को आपसी सहमति और एकता से चलाया जा सकता है। अकेले संगठन चलाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि वह लोगों को बताते हैं। अगर उनके द्वारा समन्वय समिति की बैठक की गई तो उसमें संगठन विरोधी काम नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि काम करने के तरीके पर बहस है। किसी व्यक्ति से बहस नहीं है अगर काम करने का तरीका सुधर जाए तो सब कुछ सुधर जाएगा।

कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान के बीच डॉ अजय के खिलाफ उनके अपने ही दल के लोग उन पर अपनी पार्टी को कमजोर करने के आरोप लगाते रहे हैं पिछले दिनों हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। कहा जा रहा था कि डॉ अजय कुमार का झाविमो से प्रेम खत्म नहीं हुआ है उस वक्त उन्होंने बयान दिया था कि उन्हें उन्हें मासस विधायक अरूप चटर्जी पर नहीं बल्कि झाविमो विधायक प्रदीप यादव पर भरोसा है। उस समय भी पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि उनके भरोसे की वजह क्या है। बता दें कि विवाद अरूप के वोट को लेकर हुआ था जिसमें उनपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने विपक्ष का साथ दिया है जिसके बाद मासस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी डॉक्टर अजय कुमार के बयान की कड़ी निंदा की थी।

विपक्ष द्वारा आयोजित झारखंड बंद के दौरान भी कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी उभर कर सामने आयी। सुबोधकांत का गुट अलग था जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अजय कुमार का गुट अलग मोर्चा संभाले हुए था। पार्टी के अंदर भी इसको लेकर खूब चर्चा होती रही कि आखिर इस तरह से आगे कैसे काम होगा। कई लोगों का कहना था कि एक ओर तो विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है वहीं दूसरी ओर अपनी पार्टी में ही खेमेबाजी हो रही है। इतना ही नहीं ये बातें जब आम लोगों के बीच जाती हैं तो इससे कार्यकर्ताओं को बहुत दिक्कत होती है। उन्हें अपने सीनियर नेताओं के आपसी कलह के कारण जमीन पर जनता से अपनी बात कहने में काफी परेशानी होती है।

कोयलांचल भाजपा में टंगड़ीमार पॉलिटिक्स

उमेश हेलीवाल

धनबाद में आगे कुआं तो पीछे खाई वाली स्थिति है. जिस तेजी से आम लोगों का पार्टी पर से मोहभंग हो रहा है, वह आश्चर्यजनक है. इसी जनता ने बहुत भरोसे से 4 साल पहले भाजपा पर भरोसा किया था. सांसद, विधायक और मेयर को जिताया था ताकि धनबाद कोयलांचल का विकास हो. तब आम लोग यह सोचकर खुश हुए थे कि दिल्ली, रांची और धनबाद नगर निगम में एक ही पार्टी रहेगी तो समन्वय ठीक रहेगा और विकास तेज़ गति से हो पायेगा. पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, विकास तो दूर की बात रही, आम लोग आज भी अपनी बुनियादी जरुरतों के लिए तरस रहे हैं।

एमपी, एमएलए और मेयर के झगड़े में पार्टी का बंटाधार

विपक्ष के नेता तो अब मजाक में यह भी कहने लगे हैं कि अब तो भाजपा के लोग ही विपक्ष का काम भी कर रहे हैं. एक कार्यक्रम बनाता है, दूसरा उसे फ्लॉप करने में जुट जाता है. पार्टी के अंदर जारी टंगड़ीमार पॉलिटिक्स ने भाजपा संगठन का भुरता बना दिया है.

धनबाद की भाजपा राजनीति उस चौराहे पर खड़ी है, जहां आगे कुआँ तो पीछे खाई वाली स्थिति है. जिस तेजी से आम लोगों का पार्टी पर से मोहभंग हो रहा है, वह आश्चर्यजनक है. इसी जनता ने बहुत भरोसे से 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया था. सांसद, विधायक और मेयर को जिताया था ताकि धनबाद कोयलांचल का विकास हो. तब आम लोग यह सोचकर खुश हुए थे कि दिल्ली, रांची और धनबाद नगर निगम में एक ही पार्टी रहेगी तो समन्वय ठीक रहेगा और विकास तेज़ गति से हो पायेगा.

पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, विकास तो दूर की बात रही, आम लोग आज भी अपनी बुनियादी जरुरत बिजली, पानी का ही रोना रो रहे हैं. पूरी गर्मी बिजली और पानी ने रुलाया. एक- एक मोहल्ले में 15 दिनों तक लोग पानी के लिए तरसते रहे. घंटों-घंटों लोग बिजली के लिए परेशान रहे. इधर आम लोग अपनी परेशानी से त्रस्त थे तो दूसरी ओर स्थानीय विधायक राज सिन्हा और मेयर चन्द्रशेखर अग्रवाल एक दूसरे से दुश्मनों की तरह झगड़ रहे थे. ये जन प्रतिनिधि एक दूसरे के खिलाफ ऐसी भाषा में आग उगल रहे थे, जो अमूमन विपक्ष के लोग भी किसी जनप्रतिनिधि के लिए नहीं करते. जैसे जब विधायक राज सिन्हा ने नगर निगम पर जल संकट के दौरान निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया तो मेयर चन्द्रशेखर अग्रवाल ने विधायक को बिना ज्ञान का बताते हुए कहा कि विधायक को अपना वेतन विधानसभा को लौटा देना चाहिए, क्योंकि वह कुछ नहीं जानते.

जब मेयर और विधायक इस तरह आपस में लड़ रहे थे तो इनके समर्थकों ने भी एक दूसरे के खिलाफ लाठी भांजनी शुरू कर दी. नुकसान किसका हुआ पार्टी का ही ना. विपक्ष के नेता जनता को आसानी से समझा पाए कि देखिये कैसे जन प्रतिनिधि आपस में लड़ रहे हैं. विपक्ष के नेता तो अब मजाक में यह भी कहने लगे हैं कि अब तो भाजपा के लोग ही विपक्ष का काम भी कर रहे हैं. एक कार्यक्रम बनाता है, दूसरा उसे फ्लॉप करने में जुट जाता है. पार्टी के अंदर जारी टंगड़ीमार पॉलिटिक्स ने भाजपा संगठन का भुरता बना दिया है. संगठन के लोग मूकदर्शक बने हुए हैं. संगठन में भी खेमेबाजी चरम पर है.

भाजपा के एक पदाधिकारी कहते हैं कि चन्द्रशेखर अग्रवाल की मुख्यमंत्री से करीबी जिले की राजनीति में एक रणनीति के तहत सार्वजनिक की गयी है. वो अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं. यह समझकर वर्तमान सांसद का धडा उनका धुर विरोधी हो गया है. सांसद पी एन सिंह के बयान इसी ओर इशारा भी करते हैं. ऐसी खींचतान की खबर पार्टी के रांची मुख्यालय को भी है, लेकिन सब खामोश हैं.

आपस में लड़कर इन भाजपा नेताओं के बीच ऐसी संवादहीनता पैदा हुई है, जिसका असर विकास के कामों पर दिखने लगा है. सांसद कुछ और कहते हैं, विधायक कुछ और, अधिकारियों के बीच अलग खेमेबाजी हो गयी है कि किसकी बात मानें और किसकी अनसुनी करें. अभी जिला प्रशासन में मेयर चन्द्रशेखर अग्रवाल की ज्यादा चल रही है. अग्रवाल मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, इसलिए अधिकारी उनकी ज्यादा सुनते हैं. कहा जाता है कि घोलप जैसे कई अधिकारियों का ट्रान्सफर अग्रवाल के कहने पर किया गया, इसके बाद प्रशासन पर उनका वर्चस्व बढ़ा.

भाजपा के एक पदाधिकारी कहते हैं कि चन्द्रशेखर अग्रवाल की मुख्यमंत्री से करीबी जिले की राजनीति में एक रणनीति के तहत सार्वजनिक की गयी है. वो अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं. यह समझकर वर्तमान सांसद का धडा उनका धुर विरोधी हो गया है. सांसद पी एन सिंह के बयान इसी ओर इशारा भी करते हैं. ऐसी खींचतान की खबर पार्टी के रांची मुख्यालय को भी है, लेकिन सब खामोश हैं. कोई किसी बात की जहमत नहीं लेना चाहता. धनबाद में रहने वाले प्रदेश पदाधिकारी गणेश मिश्र जैसे लोग भी चुप हैं. प्रदेश संगठन की यह चुप्पी आनेवाले समय में पार्टी का बड़ा नुकसान कर सकती है.

बात केवल धनबाद लोकसभा या धनबाद विधानसभा क्षेत्र की ही नहीं है. युवा तुर्क विधायक संजीव सिंह के जेल में होने के चलते झरिया समेत आस -पास के सभी क्षेत्रों में पार्टी का बड़ा नुकसान हो रहा है . सिंह मेंशन से आनेवाले दबंग संजीव सिंह अभी अपने ही चचेरे भाई की हत्या की साजिश के आरोप में जेल में बंद हैं. युवाओं के बीच उनका क्रेज है. व्यापारी या मजदूरों के बीच संजीव की लोकप्रियता रही है, वही एक मात्र ऐसे नेता थे, जिनकी धाख सबके बीच है. संजीव के जेल में होने की वज़ह से यह संतुलन गड़बड़ हुआ है, जिसका खामियाजा पार्टी

विधायक संजीव सिंह के जेल में होने के चलते झरिया समेत आस -पास के सभी क्षेत्रों में पार्टी का बड़ा नुकसान हो रहा है।

को अगले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है. अगर संजीव सिंह के जेल में होने की वज़ह से झरिया कमजोर हुआ तो आसपास के सिंदरी और बाघमारा विधानसभा क्षेत्रों पर भी इसका असर पड़ना तय है. भाजपा के कई नेताओं ने बताया कि संजीव सिंह और सिंह मेंशन के समर्थक धनबाद लोकसभा क्षेत्र के हर इलाके में हैं, इनके समर्थक हमेशा भाजपा को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

सिंदरी विधानसभा के विधायक फूलचंद मंडल और बाघमारा विधायक ढूल्लू महतो के बीच का झगडा भी जगजाहिर है. ढूल्लू महतो की वज़ह से व्यवसाईयों का एक बड़ा तबका भाजपा से नाराज़ है. साथ ही सिंदरी विधायक से कई बार जोर आजमाइश कर ढूल्लू महतो ने अपना एक नया सियासी समर्थक समूह बनाने का संकेत दिया है. ढूल्लू झाविमो से भाजपा में आये हैं और क्षेत्र में चर्चा है कि वह गिरिडीह लोकसभा सीट से भाजपा से टिकट नहीं मिलने की स्थिति में झामुमो से भी चुनाव लड़ सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो इस क्षेत्र में पार्टी की किरकिरी हो सकती है.

इन सबके बीच सांसद पीएन सिंह की निष्क्रियता के चलते भी पार्टी में गुटबाजी बढ़ी है. कई बार विधायक और सांसद रहे पीएन सिंह ने कोई ऐसा काम आज तक नहीं किया जिसे भाजपा प्रचारित करे. इनके वक्त 21 महत्वपूर्ण ट्रेन्स धनबाद से छिन गए. सालों साल तक एक ओवर ब्रिज भी नहीं बन सका. संसदीय क्षेत्र में सड़क की हालत सबसे जर्जर है. धनबाद से बाहर निकलते ही जर्जर सडकें हर किसी को मुंह चिढाती हैं. इस बार चर्चा है कि उम्र और निष्क्रियता की वज़ह से पीएन सिंह को पार्टी टिकट नहीं देगी, वैसे कोडरमा सांसद रविन्द्र राय और चतरा सांसद सुनील सिंह की भी नज़र धनबाद लोकसभा सीट पर है. अंदर ही अंदर मेयर चन्द्रशेखर अग्रवाल भी लोकसभा टिकट के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं.

खैर कोयलांचल भाजपा का समृद्ध अतीत अभी डरावने दौर में है. नेताओं की आपसी किचकिच ने पार्टी के समर्थकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. देश की कोयला राजधानी अँधेरे में है. ऐसे वर्तमान की कीमत विधायकों और सांसद को चुकानी पड़ सकती है.

झारखण्ड में अधमरी सी क्यों है वाम राजनीति !

श्रीधर वत्स

लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है. वामपंथी पार्टियाँ ऐसे भी नैसर्गिक विपक्ष है, वो आम जन की राजनीति करती है . ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि आखिर झारखण्ड में वाम दलों का क्षितिज क्यों सिमट रहा है ! झारखंड में लेफ्ट के दो ही विधायक हैं. आखिर क्यों?

सामाजिक असमानता की कहानियों से भरे इस प्रदेश में क्या वामपंथी पार्टियां सिकुड़ रही हैं .क्या इनका प्रभाव घट रहा हैं .आखिर कैसे इन दलों का विस्तार होगा. कैसे इनका जनाधार बढ़ेगा, इन्हीं सवालों पर रौशनी डालती यह रिपोर्ट.

जिस प्रदेश में सबसे अधिक असमानता वहां क्यों हैं दो ही वाम विधायक

झारखण्ड में वर्तमान में दो ही वामपंथी विधायक हैं. धनबाद के निरसा से मासस के अरूप चटर्जी और गिरिडीह के राजधनबार से माले के राजकुमार यादव. आखिर असमानता की कब्र पर पनपी झारखण्ड की राजनीति में वामपंथ की दाल क्यों नहीं गल रही ! क्यों पलामू, चतरा, हजारीबाग जैसे इलाके से लेफ्ट का एक भी विधायक नहीं है. भुवनेश्वर मेहता की हार के बाद सीपीआई का खाता तक नहीं खुला. क्यों लाल सलाम की वह गर्जना अब कम सुनायी देती है, जो बड़े बड़े माफियाओं को रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती थी. क्या झारखण्ड के सन्दर्भ में लाल झंडा तेज़ी से अप्रासंगिक होता जा रहा है. ऐसे कई सवाल हैं जो लेफ्ट पॉलिटिक्स की व्याख्या को नए सिरे से समझने की और संकेत करते हैं.

नक्सलियों के प्रभाव वाले जिलों में वामपंथी दल सबसे कमजोर हैसियत में हैं. वाम चिन्तक कहते हैं शायद नक्सली वामपंथियों को ही सबसे पहले कमजोर कर रहे हैं. नक्सलियों के गढ़ में भाजपा जीत जाती है लेकिन उन्हें लगता है कि अगर कोई वामपंथी जीत गया तो फिर जनता उनकी बात नहीं सुनेगी. झारखण्ड के सबसे बड़े लेफ्ट लीडर महेंद्र सिंह की हत्या नक्सलियों ने ही की, क्योंकि वह नक्सली दमन की भी उतनी ही मुखर आलोचना करते थे. ऐसे में नक्सली नेताओं को लगने लगता है कि ये तो जनता का आदमी है. जनता से इनका सीधा सम्वाद है, ऐसे में उनकी दादागीरी इलाके में नहीं चलेगी. इसलिए नक्सल प्रभाव वाले इलाके में वाम दलों की हालत शायद सबसे खस्ता है.

तीसरा एक प्रमुख कारण है खर्चीला चुनाव. लेफ्ट पार्टियां काडर बेस्ड होती हैं, उनके पास इतनी पूंजी नहीं नहीं होती, ना ही लेफ्ट के उम्मीदवारों को भाजपा या कांग्रेस की तरह चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिलता है. लेफ्ट के कार्यकर्ता आम लोगों से चंदा लेते हैं, उसी बल पर चुनाव की तैयारी करते हैं. नतीजा यह होता है कि लेफ्ट पार्टी बूथ मैनेजमेंट का खर्च तक नहीं जुटा पाती. अगर आज आपके पास करोड़ों नहीं है तो आप चुनाव लड़ने के लिए जरुरी संसाधन नहीं जुटा सकते. ना ही चुनाव कार्यालय चला सकते. वाम दलों की हार का एक बड़ा कारण उनकी संसाधनहीनता भी है.

आज की राजनीति में वोटर भी प्रलोभन के शिकार होते हैं. केश फॉर वोट के कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं. अब लोगों को शायद दल के आदर्श या आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं रहा, उन्हें बस जातीय और धन बल के संतुलन का बाज़ीगर उम्मीदवार चाहिए. ऐसे वोटर भी वाम दलों को समेटने के दोषी हैं. वाम दल के नेता जातीय आधार पर वोट नहीं मांग सकते, वो समानता की बात के आधार पर मतदाताओं का समर्थन मांगते हैं . जातीय टुकड़ों में बंटा झारखण्ड का समाज अपने जातीय नायक को ही आखिर में वोट देता है.

ऐसे में क्या है वामपंथ के लिए रास्ता ! क्या वाम दलों का मर्सिया पढ़ देना चाहिए ! इसपर माले के पूर्व विधायक विनोद सिंह कहते हैं कि रास्ता जन आन्दोलन के बीच से ही निकलेगा. वाम दलों के नेताओं को जनता से सरोकारी रिश्ते रखने होंगे . लगातार जन आन्दोलन करना होगा. लोगों को जागरूक करना होगा. वाम नेताओं को विश्वसनीय बनना होगा . जब जनता अपने नेता पर भरोसा करती है, तभी उनकी सुनती है.

युवा भी लेफ्ट से ज्यादा नहीं जुड़ रहे हैं. लेफ्ट नेताओं को कॉलेज में जा जा कर उन्हें आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स से जोड़ना होगा. जब बड़ी तादाद में युवा किसी विचार से जुड़ेंगे, तभी वाम दलों को उनकी खोयी जमीन मिल पायेगी. झारखण्ड जैसे प्रदेश में अभी भी वाम दलों के लिए काफी गुंजाईश है.

तेज प्रताप को गुस्सा क्यों आता है !

प्रणव

राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कई बार बगावती तेवर अपना लेते हैं, इधर कुछ महीनों से उन्होंने कई बार ऐसे रूप दिखाए हैं जिससे यह लगने लगा है कि वो कभी भी पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि पार्टी की स्थापना दिवस पर दोनों भाई जिस प्रकार सामने आए उससे तो यही लगता है कि फिलहाल कोई तूफान नहीं आने वाला है लेकिन अंदरखाने यह चर्चा जरूर है कि जब कुछ नहीं था तो उन्होंने पार्टी छोड़ने की धमकी क्यों दी। अपने पिता लालू यादव की तरह ही बेबाक, बिना लाग-लपेट के बोलने वाले तेजप्रताप अपने कार्यकर्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय भी हैं। वे अपने लोगों से बेहद जिंदादिली से बात करते हैं या मिलते हैं। इसलिए उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

राजद में रार

राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। लालू यादव जब से चारा घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद परिवार से दूर हैं, कई मामलों को लेकर तेजप्रताप खुलेआम बगावती सुर अख्तियार कर लेते हैं। बताया जाता है कि पार्टी में अपनी बातों को तवज्जो नहीं दिए जाने के कारण तेजप्रताप यादव खुद को ठगा हुआ या इसे अवहेलना के तौर पर देखते हैं जिसके कारण उनका गुस्सा फूट पड़ता है। अपने पिता लालू यादव की तरह ही बेबाक, बिना लाग-लपेट के बोलने वाले तेजप्रताप अपने कार्यकर्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय भी हैं। वे अपने लोगों से बेहद जिंदादिली से बात करते हैं या मिलते हैं। इधर कुछ दिनों से वे पार्टी के अंदर अपना सुझाव नहीं सुने जाने से इस कदर बिफरे हुए हैं कि पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे चुके हैं।

अपने गुस्से या खीझ को उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जाहिर किया, हालांकि उसे बाद में डिलीट कर दिया गया लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट है कि उनके अंदर कहीं न कहीं ये मलाल जरूर है कि उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं मिल रहा है जबकि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव के आगे-पीछे राजद का बड़ा से बड़ा नेता घूम रहा है।

जानकारों की मानें तो इसी दर्द को तेजप्रताप ने फेसबुक पोस्ट जरिए साझा किया और उन्होंने अपनी मां राबड़ी देवी और पापा लालू प्रसाद पर उन्हें अनसुना करने का आरोप लगाया। पोस्ट में उन्होंने राजनीति छोड़ने की घोषणा कर दी। कुछ घंटे बाद ही ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया और उसकी जगह तेज प्रताप ने नया पोस्ट किया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अकाउंट को किसी ने हैक कर उनके घर में महाभारत कराने का प्रयास किया है।

तेज प्रताप ने रिश्तेदार ओमप्रकाश यादव (भुट्टू) के बारे में फेसबुक पर लिखा, वे उनके क्षेत्र महुआ में पागल, सनकी और जोरू का गुलाम कह कर मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं। इसमें एमएलसी सुबोध राय भी हैं। जनता ने दोनों को आस्तीन का सांप बताया है, पर मम्मी मुझे ही डांटती हैं। मम्मी-पापा को कई बार बता चुका हूं। मैं बहुत प्रेशर में हूं। क्षेत्र की जनता से उन्होंने पूछा है कि इतनी प्रेशर में राजनीति हो सकती है क्या?

कई मामलों को लेकर तेजप्रताप खुलेआम बगावती सुर अख्तियार कर लेते हैं। बताया जाता है कि पार्टी में अपनी बातों को तवज्जो नहीं दिए जाने के कारण तेजप्रताप यादव खुद को ठगा हुआ या इसे अवहेलना के तौर पर देखते हैं जिसके कारण उनका गुस्सा फूट पड़ता है।

तेजप्रताप ने लिखा, इन कीड़े-मकोड़ों को चुटकी में मसल सकता हूं किन्तु मेरा पैर अपनों के कारण रुक जाता है। पार्टी व परिवार में मेरी यही स्थिति बनी रही तो अब मैं राजनीति नहीं करूंगा। महुआ की राजनीति वही लोग करेंगे जो मेरी छवि धूमिल कर रहे हैं। राजद से भुट्टू ही महुआ से चुनाव लड़ेगा।

बताया जा रहा है कि तेजप्रताप ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ में टी-पार्टी के जरिये कार्यकर्ताओं की समस्या सुनकर उसे हल करने का अभियान शुरू किया है। वहां सभी कार्यकर्ता सिर्फ भुट्टू और सुबोध की शिकायत लेकर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भुट्टू और सुबोध अफवाह फैला रहे हैं। दोनों लोगों से कहते हैं कि तेजप्रताप तो नाम के विधायक हैं। उन्हें कुछ भी नहीं आता है।

हालांकि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप चंद घंटे में ही परिवार पर लगाए अपने आरोप से पलट गए और फेसबुक पर पोस्ट किया कि 'चाचा' ने बीजेपी के साथ मिलकर हमें परिवार से तोड़ने की कोशिश की है। उनके फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया। पहले भी हम दोनों भाई और अब

मेरी मम्मी के बारे में ग़लत लिखा गया है।

हमारे बढ़ते प्रभाव से विरोधी बौखला कर निम्नस्तरीय राजनीति पर उतर आए हैं। आरएसएस और भाजपाई आईटी सेल द्वारा उनका अकाउंट हैक कर लालू-राबड़ी परिवार के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। पहले भी पिता लालू प्रसाद का फेसबुक पेज आरएसएस के एक समर्थक द्वारा हैक किया गया था।

दोनों भाइयों के बीच उभरे विवाद पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि राजद परिवार में कहीं कोई झगड़ा नहीं है। सभी लोगों का सम्मान है। तेज प्रताप यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे पर आरोप लगाया था कि प्रदेश अध्यक्ष उनकी बात नहीं सुनते और ना ही उनकी कोई सलाह मानते हैं।

भाजपा के लोग लगातार सोशल मीडिया के एकाउंट हैक करने में लगे रहते हैं। आज वे इसमें सफल हो गए।

लेकिन सियासी गलियारे में यह चर्चा भी बहुत ही तेजी से हो रही है कि शांत रहने वाले तेजप्रताप ने अपनी बात रख दी है और अपने मन की बात को सबके सामने रख कर एक तरह से उन्होंने अपनी पार्टी और परिवार को भी जता दिया है कि आनेवाले समय में उनकी अनदेखी की गई तो वे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं।

बता दें कि अभी हाल में ही उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी अनदेखी का इजहार कर दिया था और कहा था ऐसी हरकत वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने एकदम से पार्टी में खलबली मचा दी थी। बहरहाल इसको लेकर कई तरह की बहस होने लगी थी।

तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा था 'मेरा सोचना है कि मैं अर्जुन को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाऊं और खुद द्वारका चला जाऊं। अब कुछेक 'चुग्लों' को कष्ट है कि कहीं मैं किंग मेकर न कहलाऊं। ।। राधे राधे।।'

सोशल मीडिया पर तेज प्रताप के दिए गए बयान से सियासी हलकों में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे कहा जाने लगा कि मगध की जगह पर हस्तिनापुर लिखकर तेजप्रताप ने दिल्ली की गद्दी की ओर इशारा किया है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा लिखकर तेजप्रताप ने एक प्रकार से अपने छोटे भाई को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया।

लेकिन इन सब बीच तेज प्रताप पार्टी में अपनी अनदेखी को लेकर नाराजगी जताई थी और उन्होंने अपनी पत्नी, बहन मीसा भारती, और भाई का भी जिक्र किया था। उन्होंने पार्टी को बचाने की बात तो की थी लेकिन इसके लिए अनुशासन की भी बात की। तेज

सियासी गलियारे में यह चर्चा भी बहुत ही तेजी से हो रही है कि शांत रहने वाले तेजप्रताप ने अपनी बात रख दी है।

प्रताप यादव ने कहा था कि पार्टी में मुझे अपमानित किया जा रहा है। राजद में कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो गया है। उसे ठीक करने की जरूरत है। कुछ लोग हैं जो भाइयों में फूट डालकर परिवार की प्रतिष्ठा को खत्म करना चाहते हैं। वैसे नेता मेरी बात भी नहीं सुनते और पार्टी को बांटना चाहते हैं। उन्हें बर्खास्त करने की जरूरत है।

हालांकि राजद प्रवक्ता मनोज झा ने राजद के अंदर किसी घमासान से इनकार किया था। उन्होंने तेजप्रताप को बेहद सरल इंसान बताते हुए कहा कि वह पार्टी की चुनौतियों का जिक्र कर रहे। पार्टी में अनुशासन की बात कर रहे हैं। किसी कलह की बात नहीं कर रहे।

वहीं भाइयों के बीच उभरे विवाद पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि राजद परिवार में कहीं कोई झगड़ा नहीं है। सभी लोगों का सम्मान है। तेज प्रताप यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे पर आरोप लगाया था कि प्रदेश अध्यक्ष उनकी बात नहीं सुनते और ना ही उनकी कोई सलाह मानते हैं। इस मामले में तेजस्वी यादव ने कहा था कि रामचंद्र पूर्वे उनके अभिभावक हैं। तेजस्वी ने अपने बड़े भाई के बयान को किसी तरह का विवाद मानने से ही इनकार कर दिया था। तेजस्वी ने कहा था कि पार्टी हर दिन मजबूत हो रही है और हर आदमी को तरजीह भी दी जा रही है। तेज प्रताप ने जिस व्यक्ति को पद देने को कहा था, उसका मनोनयन पहले किया जा चुका है।

बाद में तेजप्रताप ने ही इस मुद्दे पर विराम लगा दिया और कहा कि दोनों भाई में कोई अनबन नहीं है। पार्टी में जिन्होंने फूट डालने का काम किया, उन्हें हमलोगों ने दूर कर दिया। ये सब सिर्फ अफवाह है। मेरे छोटे भाई अर्जुन की भूमिका में और मैं कृष्ण की भूमिका में हूं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जो लोग विवाद पैदा कर रहे हैं, उन लोगों को हम दोनों भाइयों की आपसी केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती।

भूमि अधिग्रहण पर रार आखिर क्यों ! क्या है सत्ता पक्ष का कहना और विपक्ष का फसाना ! इस मुद्दे को भावनात्मक बनाने के पीछे क्या है सियासी दलों की मंशा ! क्यों झारखण्ड की आम जनता को दो सियासी पाटों के बीच पीसा जा रहा है ! ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशता यह रिपोर्ताज ....

भूमि अधिग्रहण या सियासी ग्रहण

उदय कुमार चौहान

भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को लेकर सूबे के विपक्षी दल सड़क पर उतर गए हैं, उनकी मंशा स्पष्ट है। वे किसी भी हाल में इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते। सत्तापक्ष के दलीलों को विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। सीएनटी-एसपीटी एक्ट की तरह इस मुद्दे को भी विपक्ष भुनाने की तैयारी में है। अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इसे गरमाए हुए रखना उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। वहीं सत्तापक्ष इस पर एक बार फिर अक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए है।

चक्रव्यूह में झारखंड

विपक्ष की बंदी बेहद सफल मानी जा सकती है. पर क्या है इस बंदी का मकसद! जानकार कहते हैं केवल सियासी फायदा. दरअसल विपक्ष भी इस मुद्दे पर अपने सियासी फायदे के लिए आम जनता को गुमराह ही कर रहा है.राज्य सरकार कह रही है कि आम लोगों की जमीन केवल सरकारी योजनाओं के लिए ली जाएगी, जबकि विपक्ष राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाकर बेहद चतुराई से इसे भूमिपुत्र आदिवासियों से जोड़ रहा है.

यानि सवाल कुछ और है जवाब कुछ और ही तलाशने की कोशिश! मकसद साफ है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना साध रहा है विपक्ष.

राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण संशोधन में सामाजिक अंकेक्षण की अनिवार्यता को खत्म किया है. राज्य सरकार का तर्क है कि इस वजह से जमीन लेने की प्रक्रिया बेहद लम्बी और जटिल हो जाती है. हालांकि राज्य सरकार के इस तर्क में दम नहीं है.

अगर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण को जटिल बनाती थी तो उसे सरल करने के उपाय तलाशे जाने चाहिए. लेकिन बगैर सामाजिक अंकेक्षण के किसी जमीन को लेना कुछ सवाल तो खड़े करेगा ही साथ ही एक स्तर पर पारदर्शिता भी घटेगी.

सरकार कह रही है कि आम लोगों की जमीन केवल सरकारी योजनाओं के लिए ली जाएगी, जबकि विपक्ष राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार बेहद चतुराई से आम लोगों की जमीन छीनकर उद्योगपतियों को देने की साजिश रच रही है।

लेकिन विपक्ष के नेता अलग ही राग गाने लगे हैं, वो जनता को यह कहकर भरमा रहे हैं कि सरकार अपने लैंड बैंक को निजी घरानों के लिए रखना चाहती है और आम लोगों की जमीन अधिग्रहित कर उसे सरकारी कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल करना चाहती है जो गलत है.

इसी बहाने विपक्ष के नेता जनता को वापस सरकार के खिलाफ जल, जंगल और जमीन के सवाल पर गोलबंद कर रहे हैं.

सवाल पुर्णतः राजनीतिक है. आज की बंदी भी राजनीतिक है और इसके निहितार्थ भी शुद्ध रूप से सियासी हैं. येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना. झूठ दोनों तरफ से बोले जा रहे हैं. अब तय आम लोगों को करना है कि दोनों ही पक्षों के झूठ में से किसे अपनाना है और किसे ठुकराना है !

भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। तमाम विपक्षी दलों ने अपने-अपने स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। सत्ता पक्ष जहां संशोधन बिल को जायज ठहराते हुए अपना तर्क रख रहा है। वहीं इस बिल को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है और इसे आने वाले दिनों में राज्य का मुख्य मुद्दा बनाएगा इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 5 जुलाई के बंद से इस बात की तस्दीक होती है कि इसको लेकर विपक्ष लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है। अगले साल लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव है इसलिए इस मुद्दे को गरमा कर रखा जाएगा।

सरकार इस मुद्दे पर एक बार फिर विपक्ष से टकराव का रुख अख्तियार करती हुई दिख रही है। सरकार और बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि झारखंड के हित में यह विधेयक जरूरी है, इससे राज्य का विकास तेजी से होगा। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार चाहती है कि राज्य में सड़क, बिजली, अस्पताल, जैसी बुनियादी सुविधाओं को तेजी से पूरा किया जा सके। भाजपा का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर इसे राजनीतिक फायदे के लिए हथियार बना रही है। जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें कहीं भी पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को जमीन देने की बात नहीं है।

इन सब के बीच सीएनटी-एसपीटी और नियोजन नीति के बाद भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को लेकर जिस प्रकार सूबे की सियासत गरमा रही है उससे आने वाले दिनों में सत्तापक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने-सामने आएंगे और राज्य की जनता विकास की राह तकती रह जाएगी।

झामुमो ने मांगा जबाब

झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और इसको लेकर जनता के बीच लेकर जाने की रणनीति बना चुकी है, झारखंड बंद के दौरान जिस प्रकार पार्टी ने रणनीति बनाकर सभी दलों को इकट्ठा किया और सड़क पर उतरी इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह सरकार और बीजेपी को भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के मुद्दे पर घेरने का मन बना चुकी है। झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार बिल के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करे। यह राज्य के लिए ज्वलंत मुद्दा है, उनकी पार्टी सहित पूरे विपक्ष ने इसके खिलाफ आंदोलन किया है। गुरुजी के नेतृत्व में विपक्षी दल राष्ट्रपति से मिले और इस पर सहमति नहीं देने की गुहार लगाई थी। सरकार को इस बिल को बिना शर्त उसी तरह से वापस लेना चाहिए। बिल के विरोध में होने वाले आंदोलन के क्रम में घटने वाली घटनाओं के लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी।

जनता को बरगला रहा है विपक्ष: भाजपा

भाजपा ने भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक का विरोध करने वाले विपक्षी दलों विकास विरोधी करार दिया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर की मानें तो विपक्ष इस मुद्दे पर जनता को बरगला रहा है।यह संशोधन कॉरपोरेट नहीं, बल्कि स्कूल-अस्पताल जैसी सरकारी योजनाओं पर लागू होगा। भूमि अधिग्रहण कानून के मुआवजे और पुनर्वास के मूल प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया है।

नए प्रस्ताव से ग्राम सभा की सलाह लेते हुए एक समय सीमा में सरकारी योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण तथा चार गुना मुआवजा प्रदान करने का कार्य संभव हो पाएगा। प्रभाकर इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से सवाल करते हुए कहते हैं कि क्या वह चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए चलाई जा रही सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया जाए? इस प्रावधान से उद्योगपतियों को नहीं, बल्कि गरीब आदिवासी-मूलवासी को फायदा होगा।

@Rajneeti_Guru @gururajneeti
rajneetiguru.com
YouTube Rajneeti Guru Web News Bulletin

विधेयक के पक्ष में सरकार के तर्क

- सरकारी योजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण जल्द (छह माह में) हो सकेगा।
- योजनाएं तेजी आएगी। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरा होने में दो से तीन साल का वक्त लग जा रहा है।
- रैयतों को भूमि के एवज में मुआवजे का भुगतान अधिकतम आठ माह में हो सकेगा।
- सरकारी योजनाओं के लिए भू-अर्जन में सामाजिक प्रभावों के आकलन को समाप्त कर ग्रामसभा या स्थानीय प्राधिकार का परामर्श प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।
- निजी उपयोग अथवा उद्योग के लिए जमीन लेने पर इस संशोधन का लाभ नहीं मिलेगा।

विधेयक के पक्ष में विपक्ष के तर्क

- सरकार गरीबों और किसानों की जमीन लेकर आसानी से बड़े उद्योगपतियों को दे देगी।
- बिल को लेकर अभी तक अस्पष्ट स्थिति है। सरकार 24 घंटे में पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करे।
- बिल से राज्य में भू-माफिया को मिलेगा संरक्षण। यह कारपोरेट घरानों का हित साधने वाला है।
- इस बिल के बाद आम लोगों के पास जमीन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं बचेगा।
- जब सीएम सीएनटी, एसपीटी एक्ट में संशोधन नहीं करा पाए तो उन्होंने आंखों में धूल झोंककर कारपोरेट को जमीन देने के लिए यह तरीका अपनाया।

बिल की मंजूरी से विकास को बल: अमर बाउरी

भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है। वह चाहती है कि सरकार की ऐसी योजनाएं जिससे जनता को बुनियादी सुविधाएं दी जा सकती हैं उसे समय पर पूरा किया जा सकेगा। राज्य पहले ही बहुत पिछड़ चुका है अब देरी नहीं की जा सकती है। योजनाएं जल्द से जल्द जमीन पर उतारी जा सकें इसके लिए यह विधेयक बहुत जरूरी है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री अमर कुमार बाउरी ने भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक की राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने को सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक की स्वीकृति से न सिर्फ झारखंड में विकास को बल मिलेगा, बल्कि यहां के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उनका मानना है कि आज सारा देश झारखंड को विकास की राह पर लाने के लिए प्रयासरत है। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का राज्य सरकार का यह निर्णय आने वाले समय में काफी लाभकारी साबित होगा।

इनके लिए होगा भूमि का अधिग्रहण

भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के बाद सिर्फ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, रेल, सड़क, जलमार्ग, विद्युतीकरण, सिंचाई, जलापूर्ति पाइपलाइन, ट्रांसमिशन लाइन तथा कमजोर वर्ग के आवास के लिए भूमि का अधिग्रहण होगा।

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर राजनीति होना तय है कहा जा सकता है कि एक तरह से विपक्ष की बैठे-बिठाए बड़ा हथियार मिल गया है। सीएनटी-एसपीटी एक्ट, नियोजन नीति, स्थानीय नीति को लेकर सरकार पहले ही बैकफुट पर आ चुकी है अब एक बार फिर यह विधेयक सामने आया है इसको लेकर सत्तापक्ष भले ही यह कहे कि इससे विकास को गति मिलेगी लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें सोशल ऑडिट की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है।

> विधेयक की स्वीकृति से न सिर्फ झारखंड में विकास को बल मिलेगा, बल्कि यहां के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

झामुमो, कांग्रेस, झाविमो, राजद, लेफ्ट सहित पूरा विपक्ष इस मुद्दे को गरमाने में लगा है इन सब के बीच बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू ने भी इसको लेकर अपना तेवर दिखा दिया है। सरकार विरोधियों से तो निपट लेगी लेकिन पार्टी के अंदर ही कई नेताओं का इस मुद्दे को लेकर राय अलग है बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने कई मौकों पर सरकार के कामकाज को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है कि जमीन को लेकर सरकार के रुख से आदिवासियों में असंतोष है। सरकार को इसे संवाद के जरिए ही सुलझाना होगा। देखा जाय तो राज्य के कई हिस्सों में आदिवासियों और मूलवासियों के विस्थापन को लेकर काफी पहले से ही संघर्ष होते रहे हैं। जल,जंगल और जमीन को लेकर आदिवासी समाज का संघर्ष काफी पुराना है और इसको लेकर उनके अंदर अगर विपक्ष उबाल लाने में सफल हो जाता है तो सत्तापक्ष के लिए मिशन 2019 की लड़ाई आसान नहीं होगी।

सरकार भले ही मान कर चल रही है कि जमीन अधिग्रहण को लेकर सारा विवाद सुलझा लिया जाएगा लेकिन आदिवासी बहुल इलाकों में जमीन के सवाल पर लगातार सरकार का विरोध हो रहा है। झारखंड में विस्थापन लंबे समय से बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। पलायन राज्य की सबसे बड़ी समस्या है, हर साल हजारों की संख्या में आदिवासी- मूलवासी रोजी-रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। उधर, केंद्र और राज्य की सरकारों ने झारखंड में एक साथ कई बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बनाई है और उस पर काम भी हो रही है। अभी हाल ही में गोड्डा में आडाणी पावर प्लांट को दिए गए जमीन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं इससे किसानों और आदिवासियों में भय है कि उनकी जमीन कभी भी छीनी जा सकती है।

भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। तमाम विपक्षी दलों ने अपने-अपने स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। सत्ता पक्ष जहां संशोधन बिल को जायज ठहराते हुए अपना तर्क रख रहा है। विपक्षी दलों ने जिस प्रकार झारखंड बंद बुलाया उससे स्पष्ट हो गया है कि आनेवाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर वह जनता के बीच जाएंगे और इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगे।

भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल की मंजूरी दुर्भाग्यपूर्ण: झाविमो

पूर्व मुख्यमंत्री और झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने राष्ट्रपति द्वारा भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल 2017 को मंजूरी दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार ग्रामीण, किसानों और आदिवासियों की जमीन सरकार बिना रोक-टोक के अधिग्रहण करके पूंजीपतियों को देगी। इससे भूमिहीन हो जाएंगे और राज्य से पलायन होगा। उन्होंने कहा कि अब 2019 आने में देर नहीं है। 2019 में सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में इस कानून को लागू होने की तिथि से रद्द करेंगे। सभी अधिग्रहित जमीन रैयतों को वापस किए जाएंगे। बिना ग्राम सभा की अनुमति एवं सोशल इंपैक्ट का ध्यान रखे एक इंच भी जमीन नहीं ली जाएगी।

संशोधन आदिवासियों-मूलवासियों के खिलाफ: कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अजय ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन आदिवासियों-मूलवासियों की भावनाओं के खिलाफ है। इसको लेकर जनता में आक्रोश है। सरकार आदिवासियों एवं मूलवासियों की जमीन का अधिग्रहण कर कॉरपोरेट घरानों को औने-पौने दाम में देने की साजिश रच रही है। कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बिल में संशोधन किया गया है। राज्य सरकार ने अडाणी पवार प्लांट के लिए राज्य की ऊर्जा नीति में संशोधन कर सालाना करीब 294 करोड़ रुपये का लाभ अडाणी को पहुंचाने का काम किया है। ऐसे में 25 वर्षों में लगभग 74 सौ करोड़ रुपये का नुकसान राज्य सरकार को होगा, जिस पर महालेखाकार ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार का जन विरोधी चेहरा जनता के सामने आ गया है। सरकार द्वारा संशोधन बिल पर अब तक को स्पष्ट बयान नहीं देने से यह प्रतीत होता है की सरकार डरी हुई है और वह जानती है की जनता समय आने पर ऐसे कुकृत्यों का जमकर जवाब देगी।

चक्रव्यूह में फंसी सूबे की राजनीति

भूमि अधिग्रहण बिल के बहाने झारखंड के विपक्षी पार्टियों और सामाजिक संगठनों ने सरकार का विरोध करने के लिए एक मंच पर आने का फैसला किया है. क्या वास्तव में भूमि अधिग्रहण बिल से झारखंड के मूल वासी एवं आदिवासी का बड़ा नुकसान होने जा रहा है ?या फिर कुछ ऐसी ताकते हैं जो पर्दे के पीछे कुछ और खेल करना चाहती हैं .

राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो भूमि अधिग्रहण बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे झारखंड के मूलवासी एवं आदिवासी की अस्मिता को कोई खतरा हो क्योंकि सार्वजनिक चीजों के लिए जिस भूमि अधिग्रहण की बात की जा रही है पहले भी पुल-पुलिया, अस्पताल ,विद्यालय भवन, बिजली का तार इत्यादि सार्वजनिक कामों के लिए जमीन का अधिग्रहण होता रहा है और यह सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में पहले भी होता रहा है और आज भी होगा .

फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक आदिवासी समाज के बर्बाद होने का खतरा मंडराने लगा . दरअसल इस चक्रव्यूह को समझने के लिए घड़ी की सुई को थोड़ा पीछे घुमाना पड़ेगा -विगत चुनाव में भाजपा ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए झारखंड में पहली बार किसी गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया कुछ दिनों तक तो यह मामला अंदर ही अंदर आदिवासी विधायकों को सालता रहा लेकिन पार्टी सुप्रीमो के इस निर्णय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत किसी भी विधायक ने नहीं दिखाया लेकिन अंदर ही अंदर आग सुलगती रही. यहां तक

> अर्जुन मुंडा ने सरकार के खिलाफ अपने धनुष बाण उठा लिए। इस चक्रव्यूह का एक और बड़ा खिलाड़ी पर्दे के पीछे से अपनी चाल चल रहा था और वह खिलाड़ी है मिशनरी।

की भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को भी हाशिए पर धकेलने का काम रघुवर दास ने कर दिया .सरकार के कुछ फैसलों से असमंजस की स्थिति बनने लगी सीएनटी-एसपीटी एक्ट मे बदलाव करने का फैसला सरकार को दुविधा में डाल दिया .

दबाव बनने के चलते विधेयक को वापस तो कर लिया गया लेकिन इसी मुद्दे को लेकर सभी दलों के आदिवासी नेता एक साथ दिखाई देने लगे और बाबूलाल मरांडी जैसे कद्दावर नेता हेमंत सोरेन के सामने घुटने टेक दिए .

यहां तक कि अर्जुन मुंडा ने सरकार के खिलाफ अपने धनुष बाण उठा लिए .इस चक्रव्यूह का एक और बड़ा खिलाड़ी पर्दे के पीछे से अपनी चाल चल रहा था और वह खिलाड़ी है मिशनरी ,क्योंकि आदिवासियों के जीवन पर झारखंड के मिशनरियों का गहरा प्रभाव है इनकी जड़ें आदिवासी समाज के अंतिम पायदान तक है और इन मिशनरियों ने बखूबी इस बात का प्रचार किया कि जो राज्य आदिवासियों के लिए बना था उसके जमीन, जंगल और संसाधनों पर कारपोरेट घरानों का कब्जा कराने की नियत से सरकार उनकी जमीनों को लूटना चाहती है ,जो सच नहीं है लेकिन सीधे-साधे भोले -भाले गांव के आदिवासी अपनी पहचान को बचाने के झांसे में आ गए.

ऐसे राजनेताओं और पार्टियों को राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए अन्यथा भला तो किसी का नहीं होगा बल्कि समाज टुकड़ों में बट जाएगा और आदिवासी -गैर आदिवासी के बीच गहरी खाई भी पनप सकती है .

यदि भूमि अधिग्रहण बिल झारखंड के मूलवासी और आदिवासी को बर्बाद करने का विधेयक है तो इसका सही रास्ता क्या होगा .

इस बात को इन पार्टियों को सामने लाना पड़ेगा सिर्फ यह कह देने से कि लोगों की जमीनें लूट जा रही है काम चलने वाला नहीं है अन्यथा इतिहास माफ नहीं करेगा.

इन मिशनरियों के द्वारा बनाए हुए पिच पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मैच को अपने कब्जे में ले लिया और इस चालाकी के पीछे Congress, JVM, CPM पार्टी के लोग चुपचाप तरीके से खड़े दिख रहे हैं .ऐसा नहीं है कि इस चक्रव्यूह को वह समझ नहीं पा रहे हैं बल्कि ऐसा करना उनकी मजबूरी है तो क्या यह समझा जाए की भूमि अधिग्रहण बिल के बहाने झारखंड की राजनीति एक चक्रव्यूह में फंस गई है .

यदि सामाजिक संगठन के लोग सामने आकर ऐसे कुचक्र रचने वालों को सही आईना नहीं दिखाते हैं तो राज्य एक अंतहीन दिशा की ओर बढ़ता जाएगा. जिससे किसी भी समाज का कोई भला नहीं हो सकता है .

भूमि अधिग्रहण बिल 2017 राष्ट्रपति के मंजूरी के पश्चात झारखंड की राजनीति गरमा गई है जहां एक और राज्य की सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर खड़ी दिखाई दे रही है वहीं दूसरी ओर सत्ता के भागीदार आजसू ने भी भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार के विरोध में खड़ी नजर आ रही है वैसे देखा जाए तो सत्ता में रहते हुए आज तूने स्थानीय नीति नियोजन नीति और भूमि अधिग्रहण बिल का पुरजोर विरोध किया था लेकिन सरकार ने उनकी आवाज को नहीं सुनी आज जब मामला पूरी तरीके से गर्म हो चुका है तो सरकार को यह समझ में नहीं आ रही है कि इस मामले से निकला कैसे जाए वैसे तो भूमि अधिग्रहण बिल की अनिवार्यता और उसके विभिन्न पहलुओं को लेकर जनता के बीच अपनी बात रखने की कवायद सरकार कर रही है लेकिन राज्य के माहौल को देखते हुए ऐसा लगता है.

उनकी यह कवायद शायद सफल ना हो पाए पिछले कुछ दिनों से राज्य के सामाजिक संगठन खासकर मूलवासी आदिवासी जिस प्रकार से मकान के विरुद्ध गोलबंद हो रहे हैं दूसरी ओर आदिवासी क्षेत्रों में पत्थर गढ़ी का मामला गरमाया हुआ है उसे देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है की भूमि अधिग्रहण बिल मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां रोटी सेकना चाहती हैं और 2019 के चुनाव तक इसे गर्म आने की कोशिश भी कर रहे हैं सरकार की ओर से कोई भी मंत्री या वरिष्ठ नेता भूमि अधिग्रहण बिल पर अपनी दो टूक रहा है देने से बचना चाहता है उनकी क्या मजबूरी है यह तो नहीं पता चल रहा है लेकिन जानकार लोगों का कहना है कि राज्य के मंत्री और वरिष्ठ नेता अपनी उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं यही कारण है कि सामूहिक राय नहीं बन पा रही है.

यदि कुछ समय तक यही हालात बने रहे तो विपक्ष के लोग अपनी बात लेकर जनता को वही बात समझाने में सफल होंगे जो उनके फायदे के लायक हो ऐसा भी नहीं है की पढ़े-लिखे लोग इस सच्चाई को नहीं जानते हो फिर भी उनकी बात सुनेगा कौन क्योंकि हर बात राजनीति के कसौटी पर कसने की आदत जो हो गई है आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थानीय नीति नियोजन नीति और भूमि अधिग्रहण बिल गले की हड्डी बनती जा रही है सरकार अपनी मंशा को कैसे न्यायोचित ठहर आएगी यह तो वक्त बताएगा लेकिन वर्तमान हालात तो यही बता रहे हैं कि इन मुद्दों पर सरकार बैकफुट पर दिख रही है .

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार 3:30 साल के अपने क्रियाकलाप को जनता के बीच सही तरीके से रखने में असफल रही है मोमेंटम झारखंड पूरी तरीके से फैल रहा कोई उद्योग धंधा लगा नहीं लोगों को रोजगार मिला नहीं उसके बाद कुछ विवादित फैसले होते रहे और जनता के बुनियादी मुद्दे हाशिए पर चले गए भूख से हो रही मौतों पर जिस प्रकार सरकार अपना बयान दे रही है, उनके वरिष्ठ मंत्री स्वयं हंसी के पात्र बन गए हैं .

संबंधित अधिकारी भी इस मुद्दे पर कन्नी काटते नजर आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि सरकार मंत्री और अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी है या सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहते हैं. इन सभी बातों को जनता करीब से समझ रही है और समय आने पर जवाब भी देने के मूड में है.

अब देखना यह है कि सत्ता और विपक्ष के बीच में इन मुद्दों पर कौन बाजी मारता है और जनता किसकी बात को तवज्जो देने के मूड में है.

विशेष बहस के लिए आगे आएं सत्ता और विपक्ष : सुदेश महतो

आजसू सुप्रीमो ने कहा है कि विपक्ष को सदन में अपना पक्ष रखते हुए खुली बहस में भाग लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह संशोधन विधेयक विधानसभा से 12 अगस्त को पारित हुआ था। इस दौरान राज्य सरकार ने विधानसभा में भू-अर्जन अधिनियम-2013 की जटिल प्रक्रियाओं को कम करने की मंशा जतायी थी।

सूबे में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को लेकर मचे घमासान के बीच आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि इस मुद्दे पर विधानसभा में विशेष बहस करायी जाये। उन्होंने आजसू का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष से मिल कर यह मांग रखेगा।

श्री महतो ने कहा है कि ऐसी समस्याओं के लिए सदन ही समाधान है। विपक्ष के झारखंड बंद से समाधान का रास्ता नहीं खुला है। जमीन अधिग्रहण जैसे संवेदनशील विषय पर बहस न होना चिंतनीय है। विधानसभा में तीन मिनट में इतने गंभीर विषय पर बिल का पारित हो जाना जनता की भावना के विपरीत है।

सदन में विपक्ष न तो सरकार का ही पक्ष सुनता है और न ही अपनी बात रखता है। विपक्ष को सदन में अपना पक्ष रखते हुए खुली बहस में भाग लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह संशोधन विधेयक विधानसभा से 12 अगस्त को पारित हुआ था। इस दौरान राज्य सरकार ने विधानसभा में भू-अर्जन अधिनियम-2013 की जटिल प्रक्रियाओं को कम करने की मंशा जतायी थी। विधेयक के खिलाफ विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया था। श्री महतो ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर विधानसभा सत्र में दो दिनों का विशेष बहस हो। सत्ता-विपक्ष को नैतिक जिम्मेदारी के साथ विशेष बहस के लिए आगे आना चाहिए।

संशोधन विधेयक को लेकर पहले भी आजसू ने कड़ा विरोध किया है और आज भी हम इसके पक्ष में नहीं हैं। संशोधन झारखंड करने से पहले यहां जनभावनाओं का भी आदर होना चाहिए।

बड़ा सवाल यह है कि जब केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने इस नीति का समर्थन नहीं किया है। तो सरकार ने आखिर कैसे यह तय किया कि इस विधेयक को राज्य में लाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर सर्वदलीय एवं सामाजिक संगठनों के साथ बैठकर इस संशोधन की एक बार फिर समीक्षा करे और तब उस पर जो आम राय बनता है उसे अपनाए। सरकार को इस फैसले को जल्दबाजी में नहीं थोपना चाहिए इससे जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और सरकार के प्रति अविश्वास पनपता है।

सुदेश महतो प्रदेश के जिम्मेवार नेताओं में शुमार किये जाते हैं। उनकी इस गंभीर राय का स्वागत किया जाना चाहिए और सभी दलों को इस पर विचार करना चाहिए।

खूंटी गैंग रेप, चर्च और पत्थलगड़ी का पॉलिटिकल कॉकटेल

कुमार अमित

खूंटी गैंग रेप में सिस्टम की भयावह संवेदनहीनता चौंकाने वाली है. सिविल सोसाइटी की मानें तो अगर दूसरे प्रदेशों में यह घटना होती तो शायद सरकार गिर जाती. सोये समाज को अपने नुक्कड़ नाटक के जरिये जगाने गयी सामाजिक कार्यकर्ताओं पर घृणित और वीभत्स यौनिक हमला हुआ. लेकिन शुरू से शासन का रवैया ऐसा रहा जैसे उसकी दिलचस्पी इस मामले को दबाने में है. पीड़ितों को छुपा कर रखा गया, परिजनों तक को भी उनसे नहीं मिलने दिया गया, मीडिया से सच छुपाने की कोशिश की गयी. आखिर क्यों ! क्या असली अपराधियों को बचाने के लिए ऐसा किया गया. इस मामले में एक उग्रवादी संगठन का भी नाम आया, फिर अचानक से जांच की दिशा चर्च और पत्थलगड़ी समर्थकों की ओर मुड़ गयी. क्या जानबूझकर कोई सियासी कॉकटेल बनाया जा रहा है !

सरकार का जो रवैया रहा है वह काफी चौंकाने वाला है। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही सबों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर उसकी कार्यशैली से ऐसा लगता है कि सरकार शुरू से ही मामले को रफा-दफा करने और दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली शुरुआत से ही संदिग्ध रही है। घटना की जानकारी होने के बावजूद गैंग रेप पीड़ित 5 लड़कियों को मीडिया के सामने नहीं लाया जा रहा था जबकि प्रशासन को यह बात अच्छी तरह से पता था कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की नारा देने वाली सरकार में हुई इस दरिंदगी का कितना असर हुआ है यह राज्य के डीजीपी के बयान से समझा जा सकता है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का व्यक्तव्य देने की जगह पर वो कहते हैं कि 'तू लोग चाय नाश्ता कर और मस्त रह .....

'किसी राज्य का पुलिस कप्तान अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करें तो उस राज्य की कानून व्यवस्था कैसी होगी यह अपने आप समझा जा सकता है। राजधानी दिल्ली में ऐसी ही वारदात हुई तो सरकार जाते-जाते बची थी जबकि सरकार ने आरोपियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की थी। झारखंड में स्थिति ठीक उलट है पुलिस आरोपियों को तो नहीं पकड़ पाई है लेकिन सभी गैंग रेप पीड़ित सभी लड़कियों को कस्टडी में रखी हुई है। सरकार ने मामले को शुरु से ही इतना उलझा दिया कि इस संवेदनशील मुद्दे से सबों का ध्यान भटक जाए और पत्थलगड़ी की ओर चला जाए। जबकि इस गैंगरेप की घटना का पत्थलगड़ी से कोई लेना-देना नहीं है।

अब पुलिस- प्रशासन के रवैये पर सवाल उठने लगे हैं कि उसने शुरुआत में ही मामले को दबाने की क्यों कोशिश की क्या वह घटनास्थल पर जाने में डरती थी या उस इलाके में कार्रवाई करने से बचना चाहती थी क्योंकि कुछ महीने पहले वहां 400 से अधिक जवानों को पत्थलगड़ी समर्थकों ने बंधक बना लिया था।

> पुलिस का कहना है कि पत्थलगड़ी के पीछे भी चर्च के लोगों का हाथ है और वही भोले-भाले लोगों को बहला-फुसला कर सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों की मानें तो फादर अल्फांसो ने पीड़िताओं से अपराधियों के साथ जाने को कहा था।कर रही है। पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली शुरुआत से ही संदिग्ध रही है।

खूंटी गैंग रेप को लेकर जिस प्रकार सरकार कोचांग में जहां पांच लड़कियों के साथ बंदूक की नोक पर गैंगरेप किया गया। वहां पहुंचने में ही पुलिस को पसीने छूट गए।

पुलिस का बयान भी इस मामले को लेकर लगातार बदलता रहा और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी आदिवासी गांवों में चलने वाले पत्थलगड़ी आंदोलन से संबंधित हैं। घटना को अंजाम देने वाले अपराधी भी पत्थलगड़ी में शामिल रहे हैं।

पुलिस का मानना है कि दुष्कर्म मामले में कोचांग क्षेत्र के एक चर्च के फादर अल्फांसो की भूमिका संदिग्ध है। इसके साथ ही इसमें चर्च की भूमिका को लेकर भी कई बातें कही गई हैं। उसने सभी पीड़ितों को कहा कि जो हुआ है उसे भूल जाएं और इसे पुलिस को बताने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। पुलिस का कहना है कि पत्थलगड़ी के पीछे भी चर्च के लोगों का हाथ है और वही भोले-भाले लोगों को बहला-फुसला कर सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों की मानें तो फादर अल्फांसो ने पीड़िताओं से अपराधियों के साथ जाने को कहा था। साथ ही यह भी कहा था कि वे उन्हें कुछ समय बाद छोड़ देंगे।

हालांकि अल्फांसो ने अपराधियों से स्कूल में कार्यरत दो नन को छोड़ने को कहा था। जबकि अल्फांसो का कर्तव्य था कि वह मामले की सूचना पुलिस को देते लेकिन उन्होंने इसे दबाने की कोशिश की।

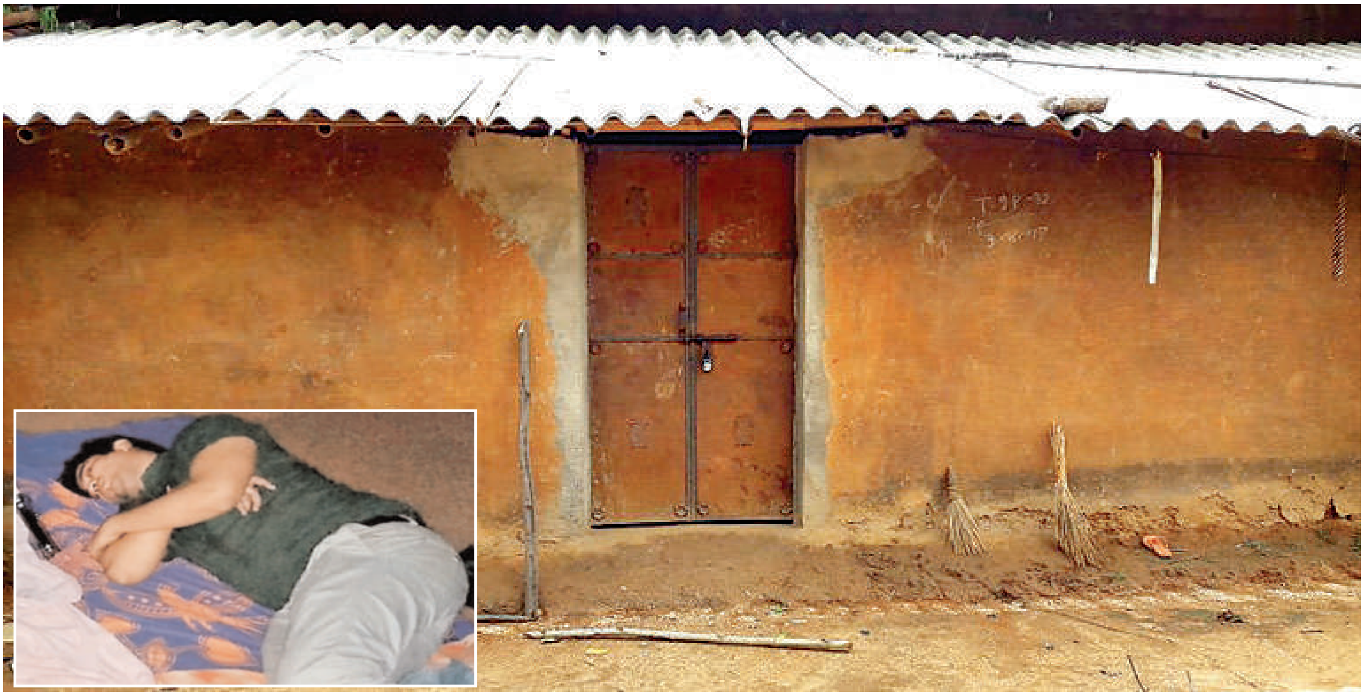

पीड़िताओं पर रहस्यमय चुप्पी..

पुलिस का कहना है कि आदिवासी लड़कियों से गैंगरेप की घटना नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) और पत्थलगड़ी के लोगों की साजिश का परिणाम है। ये लोग एनजीओ के नुक्कड़ नाटक के जरिए फैलाई जा रही जागरूकता और अपने प्रतिबंधित इलाके में आने से नाराज थे। इसके चलते आरोपी मिशनरी स्कूल में होने वाले कार्यक्रम में आ धमके और लड़कियों को नजदीक स्थित जंगल उठा ले गए। यहां पत्थलगड़ी का शीर्ष कमांडर जॉन जोहानस टीडू कई पीएलएफआई के नक्सलियों के साथ इन्हें सबक सिखाने के लिए पहले से बैठा हुआ था।

खूंटी गैंग रेप के आरोपियों की गिरफ्तार करने के लिए जैसे पुलिस ने खूंटी में अभियान चलाया इस पूरे मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब सांसद करिया मुंडा के निवास पर हमला बोलकर पत्थलगड़ी समर्थकों ने उनके तीन अंगरक्षकों को हथियार समेत अपहत कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें सुरक्षित बरामद कर लिया गया। लेकिन इसको लेकर पुलिस को भारी संख्या में फोर्स लगानी पड़ी और पूरा फोकस अपहत जवानों की ओर शिफ्ट हो गया।

उस पूरे प्रकरण में एक और व्यक्ति का नाम पुलिस लेती रही है और उनका कहना है कि रेप के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में वह बड़ा रोड़ा बना हुआ है वह है पत्थलगड़ी का स्वयंभू नेता युसूफ पूर्ति। पुलिस ने उसके खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर उसके घर की कुर्की की है पर अभी भी वह पुलिस की गिरफ्त से दूर है।

भाजपा नेताओं की मानें तो राज्य सरकार की विकास की नीति के खिलाफ कुछ उग्रवादी तथा स्थानीय ईसाई मिशनरियां एकजुट होकर स्थानीय आदिवासियों को भड़का रही हैं और खूंटी में गांवों के बाहर पत्थल गाड़ कर उस पर स्थानीय प्रशासन के प्रवेश को निषिद्ध करने की बात लिख रही हैं। प्रशासन के लोगों के गांवों के भीतर जाने पर ये गुंडे गरीब आदिवासियों को एकजुट कर उन पर हमला कर देते हैं। इन्हीं पत्थलगड़ी समर्थकों और ईसाई मिशनरी के लोगों ने मिलकर 19 जून को खूंटी में एक ईसाई मिशनरी में नुक्कड़ नाटक कर रहे समूह की पांच युवतियों का अपहरण कर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और अप्राकृतिक यौनाचार किया। पुलिस ने जब मामले में मिशन के एक पादरी समेत तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है और छह अन्य की तलाश कर रही है तो इसाई मिशनरियों ने इस नृशंस कांड पर चुप्पी साध रखी है।

> खूंटी गैंग रेप के आरोपियों की गिरफ्तार करने के लिए जैसे पुलिस ने खूंटी में अभियान चलाया इस पूरे मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब सांसद कड़िया मुंडा के निवास पर हमला बोलकर पत्थलगड़ी समर्थकों ने उनके तीन अंगरक्षकों को हथियार समेत अगवा कर लिया।

पुलिस की मानें तो सामूहिक दुष्कर्म की पूरी साजिश पत्थलगड़ी समर्थक नेता जॉर्ज जोनास किड़ो ने रची थी। क्योंकि पत्थलगड़ी वाले क्षेत्र में ये युवतियां जागरुकता फैलाने का काम कर रही थीं, जो पत्थलगड़ी समर्थकों को नहीं भाया और उनको सबक सिखाने के लिए इस घिनौने करतूत को अंजाम दिया गया। इस कांड के लिए उसने पीएलएफआई के उग्रवादियों की मदद ली और घटना को अंजाम देने का जिम्मा भी उग्रवादियों को दिया।

वहीं दूसरी ओर एक ग्रामसभा को संबोधित करते हुये पत्थलगड़ी समर्थक नेता जॉर्ज जोनास किडो ने पुलिस के आरोपों को खारिज करते हुये अपने आप को निर्दोष बताया है और कहा कि पत्थलगड़ी से आदिवासी एकजुट हो रहे हैं, जिससे डर कर सरकार ने साजिश के तहत पत्थलगड़ी समर्थकों को फंसाया है।

बाबूलाल सही या भाजपा

झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है, उन्होंने जैसे एक पत्र को लेकर भाजपा को घेरा, सत्ताधारी दल एकदम से दो-दो हाथ करने सामने आ गई। जानकार कहते हैं कि बाबूलाल ने भाजपा के दुखते रग पर जैसे हाथ रख दिया। बाबूलाल ने यूं ही नहीं इस चिट्‌ठी को सार्वजनिक तौर पर सबके सामने रखा है, वह यह जताने चाहते थे कि भाजपा के इस खेल में सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय के साजिश की बात आम जनता के बीच पहुंचे, सरकार की साख पर भी सवाल उठे, और इस मकसद में शायद वे कामयाब हो गए।

सूबे में झाविमो से भाजपा में शामिल होने वाले 6 विधायकों को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने भाजपा पर खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए एक पत्र सार्वजनिक किया है। उन्होंने दावा किया है कि झाविमो के 6 विधायकों को बीजेपी ने प्रलोभन देकर अपनी पार्टी में शामिल किया है। इसके लिए सभी विधायकों को पैसे और पद भी दिए गए। उन्होंने कहा है कि पत्र से यह बात पूरी तरह साबित हो जाता है कि मामला पूरी तरह दल-बदल का है। विलय को लेकर की जा रही बात बेबुनियाद और मनगढंत है।

इसी सिलसिले में बाबूलाल ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एक मेमोरेंडम सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में हुए पिछले असेंबली इलेक्शन के बाद उनके दल के छह विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने में सबसे बड़ी भूमिका राज्य के मौजूदा सीएम रघुवर दास की थी। इस मामले में बड़े पैमाने पर रुपयों का लेनदेन भी हुआ। बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र कुमार राय के द्वारा कथित रुपये लिखे गए एक पत्र में इस बात का जिक्र है, उस पत्र में जेवीएम छोड़कर बीजेपी जानेवाले विधायकों को 11 करोड़ रुपये दिए गए। उन्होंने कहा है कि पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि पैसे किसने दिए और किसकी निगरानी में दिए गए।

बाबूलाल ने कहा है कि चुनाव के ठीक बाद बीजेपी ने सबसे पहले पद और पैसे का सरकारी दुरुपयोग किया और उनके विधायकों को तोड़ते हुए संविधान की धज्जियां उड़ा दी। मरांडी ने कहा कि दसवीं अनुसूची में कहीं कोई इजाजत नहीं होती कि एक विधायक दल में जा सके।

निर्दलीय विधायक भी अगर किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें तो उसकी सदन से सदस्यता चली जाती है। इसमें पैसे का लेन-देन हुआ है और पद का प्रलोभन दिया गया। पद तो साफ दिखता है, उसमें दो लोगों को मंत्री बनाया, जबकि तीन लोगों को बोर्ड निगम में पद दिया गया।

यहां तक की मरांडी ने कहा है कि तीन सालों से मेहनत करते-करते एक पत्र मिला है। उस समय प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र कुमार राय थे, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा कि कुल 11 करोड़ रुपये नगद उपलब्ध कराया गया और सभी विधायकों से प्राप्ति पर्ची रघुवर दास को सौंप दी गयी। साथ ही भाजपा में आने वाले सभी झाविमो के विधायक को शेष राशि भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के तीन साल बाद रघुवर दास द्वारा उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी ली गई है।

मरांडी ने कहा है कि लोकतंत्र पर यह बड़ा कलंक है। चूंकि इसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हुए हैं, इसलिए पत्र में जितने लोगों के नाम हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। उनमें आदेशानुसार उत्तराखंड के मौजूदा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इसके अलावे सभी छह विधायकों की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और इसके लिए गवर्नर को पहल करने की जरुरत है वह इसके लिए स्पीकर को निर्देशित करें, क्योंकि इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है। यह मामला बड़े लोगों से जुड़ा है इसलिए इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए।

इस पूरे मामले पर भाजपा ने भी पलटवार किया है प्रदेश बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को जनता की अदालत में माफी मांगने को कहा है। बीजेपी ने कहा है कि वह कोर्ट का सहारा लेगी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश

बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि तीन सालों से मेहनत करते-करते एक पत्र मिला है। उस समय प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र कुमार राय थे, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा कि कुल 11 करोड़ रुपये नगद उपलब्ध कराया गया और सभी विधायकों से प्राप्ति पर्ची रघुवर दास को सौंप दी गयी।

अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी दूसरे केजरीवाल साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी को जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो भाजपा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और उन्हें कोर्ट में माफी मांगना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि खुद बाबूलाल मरांडी से उनकी फोन पर विलय को लेकर बात हुई थी।

कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि बाबूलाल मरांडी की मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है और वह अनाप-शनाप बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरांडी के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज करेंगे। विधायक अमर बाउरी ने कहा कि जब उनलोगों के निर्वाचन के बाद मरांडी के साथ पहली बैठक हुई तब पहली बार बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी में झाविमो के विलय की प्रस्ताव को रखा। बाउरी ने दावा करते हुए कहा कि इतना ही नहीं दिसंबर के अंतिम हफ्ते में मरांडी की मुलाकात दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ हुई।

उसी बैठक की बुनियाद पर मरांडी ने विधायकों के साथ विषय को रखा वहां से विलय प्रस्ताव को लेकर बात प्रारंभ हुई। बाउरी ने कहा है कि वो निर्वाचित विधायक हैं न की मनोनीत और इस बात का फैसला 2019 के असेंबली इलेक्शन में होगा।

इस मामले पर विधायक नवीन जायसवाल ने कहा है राज्य के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए राजनीतिक स्थिरता देने के मकसद से यह विलय किया गया था। मरांडी के द्वारा जारी पत्र के माध्यम से एक झूठी साजिश रची गई है आने वाले वाले समय में जनता इसका करारा जवाब देगी।

हूल विद्रोह की धरती पर सियासत की उलटबांसी

मनोज कुमार सिंह

अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले क्रांतिकारियों की धरती भोगनाडीह, बरहेट विधानसभा क्षेत्र में है। वैसे तो इस धरती पर शौर्य, पराक्रम की कई कहानियां हैं लेकिन इतिहास से इतर आज भी यह क्षेत्र झारखंड के सियासत में अलग स्थान रखती है। इस धरती ने कई कद्दावर नेताओं को पैदा किया है। थॉमस हांसदा से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक इसी धरती से आये हैं। इस सीट पर भाजपा ने अभी तक जीत दर्ज नहीं की है लेकिन आरएसएस से लेकर अन्य कई संगठन इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। इस इलाके को भगवा रंग में रंगने की तैयारी हो रही है। भाजपा हेमलाल मुर्मू के जरिए इस सीट पर कब्जा करने की कवायद में जुटी है। पर आदिवासियों और मुस्लिमों के वोट बैंक को भेदना उतना आसान नहीं है।

अंग्रेजों के जुल्मों-सितम और महाजनी प्रथा के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का बिगुल भोगनाडीह से शुरू किया गया था इसलिए मैं आपको उस धरती की ओर लिए चलता हूं जहां सिदो-कान्हू और चांद-भैरव ने उस लड़ाई की नींव रखी थी। भोगनाडीह वही धरती है जिसे संथाल समाज का मक्का कहा जाता है। कोई भी आदिवासी नेता बिना माथा टेके अपनी राजनीति की शुरुआत नहीं करता है। बरहेट विधानसभा अंतर्गत भोगनाडीह ऐसा स्थान है जिसकी धरती में कई कहानियां हैं, उस धरती को चूमने की लालसा हर आदिवासी नेता के मन में रहता है। आइए आज बरहेट विधानसभा के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं जो जाननी जरूरी हैं। इतिहास के पन्नों से आज तक की राजनीति को बयां

भाजपा, झामुमो को हराने के लिए जमीनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है और सरना आदिवासी और ईसाइयों के बीच फूट डालकर एक अलग तरह का राजनीतिक गणित सेट करना चाह रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ आदिवासी नेता भी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं।

करने के लिए वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात करवाते हैं । मैं जब उस क्रांतिकारी परिवार के सदस्यों से मिला तो ऐसा लगा कि समाज के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के बाद भी इन लोगों में कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और आज वह परिवार बिल्कुल हाशिए पर पड़े हैं। उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। बरहेट विधानसभा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति के लिए यह सीट रिजर्व है। बरहेट विधानसभा ने इस राज्य को कई कद्दावर नेता दिए हैं जिन्हें पूरा प्रदेश जानता और पहचानता है।

इस विधानसभा से राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले थॉमस हांसदा वर्षों तक संयुक्त बिहार और झारखंड के कद्दावर रहे हैं उन्हें शेरे संथाल परगना भी कहा जाता था। इसी विधानसभा सीट से हेमलाल मुर्मू कई बार विधायक बने, जो राज्य के कद्दावर आदिवासी नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं और वर्तमान में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहीं से विधायक हैं। अपने गर्भ से क्रांतिकारी योद्धाओं एवं नामी-गिरामी नेताओं को जन्म देने वाला सूबे के अन्य इलाकों की तरह विकसित नहीं है।

बता दें कि प्रत्येक वर्ष हुल दिवस पर हजारों की भीड़ यहां जमा होती है सरकारी तामझाम के साथ कार्यक्रम भी किए जाते हैं ,नेताओं का जमावड़ा लगा रहता है लेकिन धीरे- धीरे इन सारे कार्यक्रमों से आदिवासी वर्ग अपने को अलग-थलग पाने लगा है क्योंकि उन्हें यह लगता है कि यह केवल दिखावे के लिए आयोजित किया जा रहा है, न कि हूल दिवस पर

कोई ठोस नीति बनाई जा रही है। क्षेत्र की जनता वैसे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में लगातार अपना वोट देती रही है लेकिन धीरे-धीरे दूसरी पार्टियों ने भी अपना जमीन तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार इस सीट से लगातार जीत रहे हैं लेकिन उनके जीत का अंतर कम होता जा रहा है।

बरहेट विधानसभा सीट के बारे में चाय की दुकान पर लोग यह कहते नजर आए कि नेताओं को क्षेत्र के लोगों की याद तब आती है जब चुनाव नजदीक आते हैं। मोटरसाइकिल पर खड़े एक नौजवान ने अपना तेवर दिखाते हुए यह भी बतलाया कि ज्यादा समय तक हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं हम नौजवान शिक्षा और रोजगार को मुद्दा बनाने वाले उम्मीदवार का चयन करेंगे और वर्षों से चली आ रहे मिथक को भी तोड़ने का काम करेंगे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्षेत्र में आते रहते हैं लेकिन विधायक प्रतिनिधियों के प्रति लोगों में नाराजगी दिखती है।

जब राजनीति गुरु की टीम सुंदर पहाड़ी से बरहेट की ओर जा रही थी तो कई लोग जो साइकिल से कोयला बेचने का काम करते हैं मिले, उन्होंने बताया कि हेमलाल बाबू जब विधायक थे तो क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिलता था। पर अभी स्थिति वैसी नहीं है। बरहेट एक शांतिप्रिय जगह है और यहां के लोग अमन चैन के साथ अपनी जिंदगी गुजर-बसर करते हैं राजनीतिक रूप से आदिवासी और मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के चलते झारखंड मुक्ति मोर्चा यहां मजबूत स्थिति में दिखता है लेकिन कांग्रेस को वोट देने वाले भी यहां कम नहीं हैं जब थॉमस हांसदा की राजनीति चरम पर थी तो इस विधानसभा के लोगों ने उन्हें सर आंखों पर बिठाए रखा और जब कभी भी वह सांसद का चुनाव लड़े तो बिना दल या पार्टी का सिंबल देखे बरहेट के लोगों ने उनको वोट दिया और जिताया भी। लोग कहते हैं कि वह समय कुछ और था। लेकिन वर्तमान राजनीति में पिछले समीकरणों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि यहां निर्णायक मत पहाड़िया जनजाति का भी है यहां के पहाड़िया राजनीतिक रूप से सजग दिखते हैं यही कारण है कि झाविमो से चुनाव लड़ने वाले सिमोन मालतो ने भी अपनी ठीक-ठाक उपस्थिति दर्ज कराई थी यह अलग बात है कि राजनीतिक समीकरणों के चलते झामुमो यहां चुनाव जीतता रहा है। भाजपा लगातार कई वर्षों से क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही है।

गैर आदिवासी हिंदू मत भाजपा के पक्ष में ही खड़े दिखते हैं उसके अलावा पहाड़िया जनजाति के कुछ नेताओं के सक्रिय भागीदारी के चलते भाजपा ने अपना प्रभाव पहाड़ों पर मजबूत कर लिया है यदि आदिवासी वोटों में किसी कारण से बिखराव हो जाता है तो यहां का चुनावी गणित बदलते देर नहीं लगेगी। चूंकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र से विधायक हैं इसलिए भाजपा, झामुमो को हराने के लिए जमीनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है और सरना आदिवासी और ईसाइयों के बीच फूट डालकर एक अलग तरह का राजनीतिक गणित सेट करना चाह रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ आदिवासी नेता भी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हेमलाल मुर्मू जो कई बार क्षेत्र से विधायक रहे हैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। उनके भाजपा में जाने से क्षेत्र का समीकरण बदल सकता है क्योंकि बरहेट विधानसभा को सबसे करीब से समझने और जानने वाले एकमात्र नेता वही हैं इसलिए कहा जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को हेमलाला मुर्मू से चुनाव जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी।

गोड्डा लोकसभा 2019

भाजपा या महागठबंधन !

जितेन्द्र दुबे

लोकसभा चुनाव 2019 के नजदीक आने की आहट सुनाई देने लगी है। राजनीतिक दलों के धरना - प्रर्दशन और बंदी की तैयारी बता रही है कि वो चुनावी मैदान में जाने के लिए वार्मअप होने लगे है। संताल परगना के अंतर्गत आने वाले तीन लोकसभा क्षेत्र दुमका, राजमहल (दोनों सुरक्षित) और गोड्डा है. जिसमें से गोड्डा सीट पर भाजपा काबिज है, जबकि शेष दोनों क्षेत्रों पर झामुमो और कांग्रेस का कब्जा है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र पर अधिकांश समय कांग्रेस और भाजपा के ही प्रत्याशी जीतते आए हैं । वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे इस सीट पर दूसरी बार कांग्रेस प्रत्याशी फुरकान अंसारी को मात देकर काबिज हुए हैं । आगामी चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति मे मजबूत नेता की पहचान रखने वाले विधायक प्रदीप यादव भी महागठबंधन का उम्मीदवार बनने के लिए जोड़-तोड़ की गोटी बिछा रहे हैं । श्री यादव 2000 के चुनाव मे भाजपा प्रत्याशी के रूप मे इस सीट से सांसद भी रह चुके है।

संयुक्त विपक्ष का प्रत्याशी बनने के लिए प्रदीप यादव और फुरकान अंसारी दोनों अपने दांव चल रहे हैं। इस सीट पर मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटरों की निर्णायक भूमिका होने के कारण सभी दल इस समीकरण को तय करने के बाद ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करते हैं । यही कारण है कि एक दो बार को छोड़ दिया जाए तो हर बार इसी तीन समुदाय से आने वाले प्रत्याशी ही गोड्डा लोकसभा की सीट पर अपना डंका बजाते आए हैं ।

> गोड्डा मे प्रस्तावित अडानी पावर प्लांट आने वाजे समय में विकास के मामले में मील का पत्थर साबित होगा

भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे सीटिंग एमपी हैं , अगर सब कुछ सामान्य रहा तो लगातार तीसरी बार इस सीट पर अपनी किस्मत आजमाऐंगे।

विकास की कसौटी पर अगर गोड्डा को परखा जाए तो यकीनन संताल परगना के सबसे एक्टिव सांसद के रूप मे निशिकांत दुबे का ही नाम आता है। संताल परगना के साहिबगंज में प्रस्तावित गंगा पुल और बंदरगाह निर्माण का मामला हो या फिर गोड्डा मे रेल लाने की बात हो या देवघर मे एम्स, हवाई अड्डा और बाबा मंदिर के विकास का मामला हो. सांसद का प्रयास काबिले तारिफ है। गोड्डा में इन्होंने रेल के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और यह घोषणा भी की कि चुनाव में नामांकन करने के लिए ट्रेन पर ही सवार होकर आउंगा।

गोड्डा मे प्रस्तावित अडानी पावर प्लांट आने वाजे समय में विकास के मामले में मील का पत्थर साबित होगा। इत्र उद्योग, सैनिक स्कूल, डेयरी प्लांट सहित अन्य कई घोषणाएं अभी तक सरजमीं से बहुत दूर हैं. सांसद की ये बातें हवा हवाई साबित करने में विपक्ष कोई कोर कसर नही छोड़ेगा।

चुनाव नजदीक आते आते स्थानीय मुद्दे भी हावी हो जाते हैं । ऐसे मुद्दे पर स्थानीय सांसद फिसड्डी साबित हुए हैं ।

बिजली की समस्या इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक प्रमुख समस्या बन गयी है। बिजली की आपूर्ति बराबर बाधित रहने के कारण आम जनों में जबदस्त आक्रोश व्याप्त है। कुल मिलाकर यह चुनाव सांसद बनाम अन्य पर ही लड़ा जायेगा।

An ISO 22000-2005 Certified Company
सिलसिला स्वाद का, एक नई पहचान के साथ.
Aakash
Namkeen
Ek aisa swad, Jo har pal rahe yaad
www.aakashnamkeen.com
Estd
Indore's Legacy
1936
Mega Super For Jharkhand
M/S. Venus Agencies , G-8, Narsaria Tower, OPP. Lalpur Thana
H.B.Road, Ranchi- 834001, Ph- 8709835046

EducationGuru
Examine, Experience, Explore
Action is the foundational key to all success.
www.educationguru.co.in/

चाNAKYA STUDY CENTER

सफलता बेमिसाल...

चाणक्या के 500 प्रतियोगी सफल

- दारोगा बहाली में बेहतरीन सफलता
- वनरक्षी, एसएससी, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव तथा आईआरबी उम्मीदवारों के लिए विशेष बैच.

चाणक्या स्टडी सेंटर में कैरियर परीक्षा की तैयारी कराते वक्त प्रतियोगियों के लिए हम व्यक्तिपरक और सब्जेक्टिव दोनों ही बातों का ख्याल रखतें हैं, इसलिए हमारी सफलता की दर सबसे अधिक है

निदेशक , चाणक्या स्टडी सेंटर, रांची

श्रवण कुमार सिंह

निदेशक , चाणक्या स्टडी सेंटर, रांची

धन्यवाद ग्राहको...
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम
HP
आपके भरोसे ने हमें बनाया
संथालपरगना का सबसे भरोसेमंद और
सबसे तेज विकास करने वाला पेट्रोल पंप.
QUALITY
100%
GUARANTEED
100% प्योरिटी और सही मात्रा की गारंटी
समर्पित सेवा ही हमारी पहचान
M/S ALAM PETROLEUM
TALBONA UDHWA BAZAR (SBG).
M/S Alam Petroleum
Talbona, Udhwa Bazar (Sahebganj)